[Shri Ravindra Varma]

session. So, we will now take up Item No. 28.

16.40 hrs.

MOTION *RE.* GROWING STUDENT UNREST IN UNIVERSITIES

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा विश्वविद्यालयों में तथा विश्वविद्यालय समझे जाने वाले उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में बढ़ते हुए छात्र असंतोष पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से सिफारिश करती है कि असन्तोष के कारणों को दूर करने के लिए समुचित पग उठाये जायें।"

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Sir, what about item No. 27? Why are you skipping over it?

MR. SPEAKER: Item No. 28 is listed to be taken up at 4 O'Clock. The House has agreed to postpone it by half an hour.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Even then the House would like to have some indication of the thinking of the Government in the matter. I am not interested only in a discussion as such. It can go over to the next session.

MR. SPEAKER: When the matter was taken up and postponed, you must have been present.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Let him tell the House that the main recommendations of the Verghese Committee regarding autonomy will be implemented as speedily as possible. At least that assurance should be given.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: No, there may be different of opinion on the Verghese Committee's report. It should be examined.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Otherwise, bureaucracy is acting in its own way. Let him give some indication as to what Government are going to do in the matter. It is a very serious matter.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Government has said so many times that it is going to give autonomy.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): Government stands by its basic commitment to grant autonomy to the broadcasting media, but the shape and kind of its autonomy would depend on the debate in the House. I was keen to have the debate in this session itself, but somehow it has not been possible. So far as the Government is concerned, Government stands by its commitment of granting autonomy.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं ने सदन के सामने जो प्रस्ताव पेश किया है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और उस का सम्बन्ध देश की एक बहुत बड़ी समस्या से है। मुझे भय है कि अगर हम ने इस समस्या को जल्दी से न सुलझाया तो हो सकता है कि देश का प्रजातंत्र ख़तरे में पड़ जाय और ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ जाय, यहां तक कि वह हमारे काबू से बाहर हो जाय। इस लिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करे और इस को हल करन के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाय।

इस बारे में मार्च, और अप्रैल, 1978 के दौरान पूछे गए सवालों के मंत्री महोदय ने जो जवाब दिये, उनसे यह प्रकट हुआ कि पिछल एक वर्ष में जितनी बार हिन्दुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ बन्द हुई हैं, शायद उतनी बार आज तक कभी बन्द नहीं हुई हैं। पहल भी कभी कभी यूनिवर्सिटीज बन्द होती थीं, लेकिन अब शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो, जो कभी न कभी बन्द न हुई हो और शायद ही कोई प्रदेश बचा हो, जहां कोई यूनिवर्सिटी बन्द न हुई हो। इस क आतारक्त एक और गम्भीर बात यह देखने में आ रही है कि यूनिवर्सिटीज के बन्द होने के साथ साथ वायलेंस की घटनायें भी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं।

मैं समझता हूं कि सदन में इधर बठने वाले सदस्य हों या उधर बठने वाले सदस्य हों, इस बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं कि आज जो स्थिति है, वह संतोषजनक नहीं है, वह एक चिन्ताजनक स्थिति है, और इस में सुधार किया जाना चाहिए। विद्या

विश्वों की अनरेस्ट का प्रश्न किसी पार्टी का सवाल नहीं है, यह जनता पार्टी या इस सरकार का सवाल नहीं है, बल्कि यह सारे राष्ट्र का सवाल है। इस लिए इस सदन की यह जिम्मेदारी है कि हम आज की बहस में कोई ऐसा रास्ता निकालें, जिससे विश्वविद्यालयों में शान्ति स्थापित हो और वहां एक ऐकडेमिक एटमास्फियर पदा हो।

मैं समझता हूं कि एक सब से बड़ा कारण यह है कि इमर्जेंसी के दौरान, और उससे कुछ दिन पहले, विद्यार्थियों ने देश में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए एक जबर्दस्त आन्दोलन किया था। और उनका एक जबर्दस्त भाग इस आंदोलन में रहा। देश में पुनः प्रजातंत्र का निर्माण हुआ, हमें दोबारा आजादी मिली—इसमें विद्यार्थियों का भी बहुत बड़ा भाग रहा है। मैं कहूंगा कि अगर विद्यार्थी इसमें अगुवा न होते, श्री जयप्रकाश नारायण की काल के साथ अगर विद्यार्थी न चलते तो शायद आज जिस स्थिति में यह देश है उस स्थिति में वह न होता। उन्होंने अपना तन, मन और धन दांव पर लगाकर, अपना जीवन न्योछावर करने के लिए तैयार हो कर एक काम किया, इस आशा के साथ कि अगर देश का राजनीतिक वातावरण बदलेगा तो विश्वविद्यालयों का वातावरण भी बदलेगा। आज मैं समझता हूं कि स्टूडेण्ट्स अनरेस्ट का एक जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि देश का राजनीतिक वातावरण तो बदल गया, देश में प्रजातंत्र तो आ गया लेकिन दुर्भाग्य से यूनिवर्सिटीज का ढांचा वैसा का वैसा ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इस देश में प्रेस की फ्रीडम तो आ गई, अदालतों की फ्रीडम भी आ गई और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी हो गई लेकिन यूनिवर्सिटीज का ढांचा वही रहा। अगर उसमें कोई परिवर्तन आया भी तो बहुत थोड़ा आया। विद्यार्थियों की जो आशायें थीं कि हम भी ताजी हवा में रहेंगे वह हवा उनको नहीं मिली। तो इसमें एक यह चीज है।

आज देश के कोने कोने में मांग हो रही है कि इमर्जेंसी के दिनों में यूनिवर्सिटीज में जो कुछ हुआ, जिन्होंने वह किया, उसकी जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए, उनकी सजा होनी चाहिए और उनको वहां से हटाना चाहिए। आपने शाह कमीशन बिठाया आज वहां पर शाह कमीशन की रिपोर्ट भी रखी गई, देश में आशा बनी कि जिन लोगों ने कसूर किया है उनको सजा दी जाएगी ताकि आने वाली सरकार, चाहे इधर की हो या उधर की हो, वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे देश में फिर प्रजातंत्र खतरे में पड़े। यह तो हुआ लेकिन उसके साथ-साथ यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं हुआ। मुझे याद है जिन वाइस चांसलर ने एक्सेसेज की थीं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कत्ल किया, मैं दिल्ली जेल में था वहां पर 12 साल के बच्चे भी मेरे साथ थे, जब हमको कोई वकील नहीं मिला जो कि हाईकोर्ट में पेटीशन ले जाता कि उन बच्चों के लिए परीक्षा दिलाने का इन्तजाम होना चाहिए तो मैंने उनकी तरफ से आर्ग्यू किया, मैं भी डिटेन्यू था और वे भी डिटेन्यू थे, वकील ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी वाले चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने लिख कर भेजा कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। बच्चों ने कहा कि हमारी परीक्षायें आप जेल में ले लीजिए, उन्होंने कहा कि हमें पुलिस कस्टडी में परीक्षा देने दीजिए लेकिन वाइस चांसलर नहीं माने और कहा कि सिक्योरिटी के लिए यह बहुत बड़ा रिस्क होगा। इस तरह से दिल्ली में करीब 12-13 सौ विद्यार्थियों के जीवन को धक्का लगाने वाले जो लोग हैं उनके लिए मंत्री महोदय यह कह कर छुटकारा नहीं कर सकते कि आटोनामस बाडी है, आटोनामस यूनिवर्सिटी है। अगर कहीं पर हड़ताल हो गई, कोई यूनिवर्सिटी बन्द हो गई तो उसके दो ही कारण सरकार देती है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है और जो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जैसे दिल्ली, बनारस, अलीगढ़, वहां की हालत भी बड़ी खराब है, वहां के लिए भी सरकार कहती है कि वह आटोनामस है। वह आटोनामस तो है लेकिन आप किस मर्ज की दवा हैं? अगर आप इस चीज को नहीं कर सकते तो आपकी आज्ञा कभी भी फलीभूत नहीं होगी कि देश में शांति पैदा हो। ऐसा कभी नहीं होगा। आप को एक वातावरण बनाना होगा। एक तरह से इस गाड़ी के चार पहिए हैं—एडमिनिस्ट्रेशन, जिस में वाइस चांसलर हैं, विद्यार्थी, टीचर्स और कर्मचारी। आज टीचर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, विद्यार्थियों के साथ कोई रैपर्ट नहीं है, सब अलग-अलग होते जा रहे हैं और एमर्जेंसी के बाद यह "गल्फ" बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में मैं जानता हूं—वहां जो घटनायें हुईं—यहां एक बात मैं पहले कह देना चाहता हूं और सारा सदन भी इस बात से सहमत होगा कि विद्यार्थियों की मांगें चाहे कितनी जायज हों, लेकिन उन को वायलेंस करने का अधिकार नहीं है, वायलेंस हरगिज नहीं होना चाहिए, जहां कहीं भी वायलेंस होगा, मैं उन को डिसएप्रूव करूंगा, कण्डेम करूंगा और मैंने पहले किया भी है। दिल्ली में जब एक बार घटना हुई थी, जिस में वाइस-चांसलर का आफिस बन्द कर दिया गया था, मैंने यहां खड़े हो कर उस को कण्डेम किया था और उस के बाद उन बच्चों को डांटा, समझाया और कहा कि यह हमारा फ्रीडम नहीं है।

लेकिन इस दफा क्या हुआ—वायलेंस किसी ने किया और जिम्मेदार किसी को ठहराया गया। मंत्री महोदय आज उस के बारे में सोचने को भी तैयार नहीं हैं। दिल्ली के तमाम मेम्बर पार्लियामेण्ट कह रहे हैं और जो एविडेंस आई है, वह भी यही कहती है कि लड़ाई झगड़ा किसी ने किया, जिम्मेदार किसी को ठहराया गया। यूनिवर्सिटी ने जो कमेटी बनाई, वह भी कमिटेड लोगों की थी, कमिटेड होने के बाद भी जो गवाहियां दी गईं, उस में यही कहा गया है कि जो बच्चे निकाले गये हैं, मैं तो उस को रोक रहे थे, वायलेंस नहीं कर रहे थे, जिन के खिलाफ नाम लिए गये, उन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिन्होंने डेपु-आफिस में आग लगाई, उन के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं—क्या यह सिलबर केस आज

[श्री कंवर लाल गुप्त]

डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ? इस एटीचूड से आप किस तरह से उनकी भावनाओं को शान्त कर सकते हैं ? मुझे दुख है, मंत्री महोदय ने एक ही बात ले ली है—मुझे क्षमा करें, यहां पर मेरी सरकार है, अपनी सरकार के प्रति मुझे इतने कड़े शब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन मेरी भावना ऐसी है कि मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूं । उन का कहना है कि या तो पुलिस उन को ठीक करेगी या जो वाइस-चांसलर हैं, जो कमिटेड हैं, उन के हाथ में बच्चों को आप ने सौंप दिया है । आप यह कह रहे हैं कि यह आटोनामस है, मैं इस में कुछ नहीं कर सकता हूं—आप को अपने इस रवैये को बदलना चाहिए । वाइस चांसलर इस बात को जानते हैं कि वे चाहे जो करें, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता है । इसलिए अगर कानून को भी बदलना पड़े, तो आप को बदलना चाहिए—मैं यह मांग इस सदन में आप से करता हूं । यह सदन करोड़ों रुपया आप के लिए स्वीकार करता है, यू० जी० सी० और यूनीवर्सिटीज के लिए हम करोड़ों रुपया देते हैं, क्या यह पैसा हम इस लिये देते हैं कि वे प्रजातन्त्र का हनन करें, बच्चों पर लाठियां चलवायें, उन को निकाल दिया जाय, उन के साथ पार्शियलिटी करें, डिस्क्रिमिनेशन करें और उस के बाद भी वे लोग यहां पर बने रहें—यह सदन इन बातों के लिए पैसा नहीं देता है ।

16.49 hrs.

[SHRI RAM MURTI *in the Chair*]

मैं माननीय मंत्री महोदय को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे अपने रवैये को बदलें और रवैया बदल कर यह आर्गुमेण्ट न करें कि वह आटोनामस है । आप यहां पर हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, आप यह देखिए कि जो इस तरह के लोग हैं उन को सजा दी जाय, उन को हटाया जाय । यहां एक बात और कह देना चाहता हूं—अगर लड़के गल्ती करते हैं तो आप उन को भी सजा दीजिए, मुझे उस में कोई एतराज नहीं है । हम कभी नहीं चाहेंगे कि वे किसी भी तरह का वायलेंस करें । हम चाहेंगे कि एकेडेमिक एटमास्फीयर बने, अनुशासन रहना चाहिए, कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों में और बड़ों में थोड़ा फर्क होता है ।

अभी स्टीफन साहब यहां कह गये कि शाह कमीशन बकवास है । राज्य सभा में तो मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा गालियां दी गईं और कहा गया है कि हम इस को जनता में ले जायेंगे, यदि कुछ भी कार्यवाही की गई । यह सदन इन बातों को शान्ति के साथ सुन सकता है, क्योंकि हम थोड़े मैच्योर्ड हैं, हमें इस तरह की बातें सुनने की आदत है । लेकिन उन का क्या मतलब है—वे हम को धमकी देना चाहते हैं कि उस का मुकाबला गोलियों से होगा । लेकिन बच्चे इतने मैच्योर्ड नहीं होते हैं, उनके दिल में जजबा है । उनको किसी ने आज तक बैठ कर गाइड नहीं किया और उन की आशाओं पर पानी फेर दिया । वे निराशा के वातावरण में अंधेरे में घूम रहे हैं और यही प्रमुख कारण है जिस से अनरेस्ट फैलता जा रहा है । इस के लिए आप आल इण्डिया लेविल पर कोई मिकेनिज्म, कोई मशीनरी बना कर दूर करें । मेरा सुझाव यह है कि अगर बच्चों की कुछ शिकायतें हैं, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की कुछ शिकायतें हैं वाइस-चान्सलर के खिलाफ़ तो उन को उस मशीनरी को सुपुर्द कर दीजिए और वह मशीनरी उन को देखे और उन की जांच करे और जांच करने के बाद अगर वाइस चान्सलर की गलती है तो उन को सजा दी जाए और अगर विद्यार्थियों की ग़लती है तो उन को सजा दें । लेकिन कहीं कसूरवार वाइस-चान्सलर है, तो वही कमेटी बनाएगा, वही आडम्बर करेगा और सजा भी वही देगा । जिस को सजा देनी चाहिए उस को सजा नहीं दी जाती है, तो इस तरह से शान्ति पैदा नहीं होगी । एक कारण तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स अनरेस्ट का यह है ।

दूसरा कारण यह है कि विद्यार्थियों के सामने एक अंधकार है और उन को पता नहीं कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है, वे अंधकार में रहते हैं । There is a complete darkness before them. बी० ए० और एम० ए० करने के बाद भी उन को दोनों समय का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस का कोई विश्वास उनको नहीं है । इस तरह की आज स्थिति है । हम ने वायदा किया है, जनता पार्टी ने वायदा किया है कि दस साल के अन्दर हम हर एक को एम्पलायमेंट देंगे । मेरा विश्वास है कि हम देंगे लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि वे जो कन्सर्न्ड मिनिस्टर्स हैं उन को कहें कि दस साल का अर्सा तो बहुत लम्बा अर्सा है, हम एक फेज्ड प्रोग्राम बनाएं कि हर साल कितने लोगों को हम एम्प्लायमेंट देंगे और वह टार्गेट आप एचीव करते जाएं । जब इस तरह की बात स्टूडेंट्स के सामने आएगी, तो उन में एक विश्वास पैदा होगा और विद्यार्थियों में कुछ पढ़ने की, लिखने की और कुछ अनुशासन की बात भी आएगी, नहीं तो आज जो सारा ताना बाना है, वह वैसा ही झीना रहेगा ।

एक चीज और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जब से मैं पैदा हुआ हूं, तब से मैं सुनता आ रहा हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति बड़ी खराब है । जवाहरलाल नेहरू जी ने भी यही कहा और जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने भी यही कहा कि शिक्षा पद्धति में बदल आनी चाहिए और जब इन्दिरा जी आईं तो उन्होंने भी यही कहा और वे यही कहती रहीं । अब हम भी यही कह रहे हैं कि शिक्षा पद्धति में बदल आनी चाहिए । इस के लिए पहले कमीशन भी बैठाए गये, दो तीन कमीशन बने और उन्होंने बहुत सारी रिपोर्टें दीं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए । मेरा ख्याल है कि वे रिपोर्टें कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हैं । अब हमें भी 13 महीने हो गये हैं और क्या हम भी जिस तरह से पहली सरकार चलती थी, उसी तरह से चलेंगे । हम ने शिक्षा पद्धति में क्या बदल किया है । पहले 10 प्लस 2 प्लस 3 चला रही ।

उस के बाद आपने 8 प्लस 4 और प्लस कुछ और किया है।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : यह नहीं हुआ है।

श्री कंवरलाल गुप्त : अब आपने 8 प्लस 4 प्लस कुछ और किया है। 10 प्लस कुछ है या 12 प्लस कुछ है, यह हमें और हिन्दुस्तान में लोगों को साफ़ नहीं है। कहीं कुछ प्लस है और कहीं कुछ प्लस लेकिन टोटल वही 15 साल होता है 10 प्लस 2 प्लस 3 यह पहले आया था और आपने जो किया उस के आंकड़े अभी ठीक से मालूम नहीं हैं। बाद में यह कहा कि इस का स्टेट्स पर छोड़ देंगे और स्टेट जैसा चाहें वैसा करें। इसका नतीजा यह होगा कि कहीं 10 प्लस 2 होगा और कहीं कुछ और होगा। This is a confusion. I think the Government should have a clear picture in its own mind what type of education they want and the amendment changes they want to suggest to the people.

हम चाहते हैं कि यह चीज क्लीयर होनी चाहिए 13 महीने में यह चीज क्लीयर नहीं हुई है। मेरे पास एक विद्यार्थी के पिता जी आये थे। उन्होंने कहा कि सुना है कि स्टूडेंट्स अनरेस्ट पर चर्चा होगी। मैंने एन० सी० आर० टी० पर पहले एक सवाल उठाया था कि एक से लेकर बारहवीं कक्षा तक कितनी किताबें उपलब्ध हैं?

"Out of 60 textbooks prescribed by the NCERT for classes I to VIII, only 12 are made available. The position for Classes IX, X and XI is still worse. For XII Standard, for which the students have to appear for the Board Examination in March, 1979, except English and Hindi textbooks, no other textbook has so far been compiled for printing. Since the Publications Division at Patiala House are the sole distributing agents of the NCERT, it is not known what the Sales Wing of the NCERT are doing."

यह हालत है। सभापति महोदय, यह सवाल मैंने एक साल पहले उठाया था और मांग की थी कि किताबें छपनी चाहिएं। उस समय माननीय मंत्री जी ने कहा था कि किताबें छप जाएंगी लेकिन अभी तक बहुत सारी किताबें उपलब्ध नहीं हैं। जब अब बच्चों के पास किताबें नहीं होंगी तो वे पढ़ेंगे क्या?

सभापति जी आज भी बहुत सी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर नहीं हैं। मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जवाब दिया था कि उपयुक्त आदमी नहीं मिल रहे हैं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : अब मिल गये हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : अगर यहां बहस होने के बाद मिलते हैं तो बात दूसरी है। आपने यहां स्वयं कहा था कि उपयुक्त आदमी नहीं मिल रहे हैं।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने स्वयं यह कहा है कि स्टूडेंट्स में जो आज अनरेस्ट है वह इसलिए है कि उनके सामने अंधकार है। यह अंधकार इसलिए भी बढ़ता जा रहा है कि हमारी शिक्षा की क्वालिटी गिरती जा रही है। हमारे यहां वाइस चांसलर नहीं मिलते हैं जो कि अच्छे हों। यह बात राष्ट्रपति जी ने पब्लिकली कही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये सब बातें कौन ठीक करेगा? ये बातें ठीक होनी चाहिए।

17.00

सभापति महोदय, एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे में स्टडी की गई है कि टीचर्स बनने के बाद लोग कितनी स्टडी करके आते हैं और कितना वे पढ़ते हैं। उस सर्वे में यह रिपोर्ट आई है कि 56 परसेंट टीचर्स अपोइंटमेंट के बाद पढ़ते हैं। पहले वे किताबों को देखते नहीं कि क्या किताबें हैं। इसका परिणाम यह है कि हमारी जो शिक्षा है वह ओबसोलीट होती जा रही है और समय के हिसाब से आगे नहीं चल पा रही है। समय आगे बढ़ता जा रहा है और शिक्षा वहीं की वहीं है। नतीजा यह होता है कि दोनों का मेल न होने से विद्यार्थियों में अनरेस्ट पैदा होता है। इसके लिए हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि इस तरह की चीज ठीक हो। हमारे प्रेजेन्ट सिस्टम आफ एजूकेशन में भी बदल होनी चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारा एजूकेशन सिस्टम समय के हिसाब से है या नहीं। इसका एक और कारण है इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं और सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। यूनिवर्सिटियों में पोलिटिकल पार्टीज का इंटरफीयरेंस होता है। यह चीज भी इसके लिए बहुत ज्यादा हद तक जिम्मेदार है। हम उनको मिसयूज करेंगे, इस तरीके से इंटरफीयर करेंगे तो वहां शान्ति नहीं बनी रह सकती है। बिहार में रिजर्वेशन का सवाल आया। विद्यार्थियों में इस को ले कर कोलाहल मच गया और वहां के सभी विश्वविद्यालय बन्द हो गए। उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। पोलिटिकल एटमसफीयर जो बाहर रहता है वह यूनिवर्सिटियों में भी आता ही है। मुझे डर है कि हमारे इधर के भाई अब कोई नहीं हैं। सभी बैंच खाली हैं हो सकता है कि एक डिटमिंड एफर्ट इनकी तरफ से हो अब के कम दिल्ली में शाह कमिशन की रिपोर्ट पर जो कार्रवाई होगी उसको ले कर। उस में विद्यार्थियों का उपयोग करके देश में वायोलेंस पैदा करने की एक कान्सिपरेसी हो सकती है। उसके लिए भी आपको सतर्क रहना चाहिए। उनके अन्दर बहुत से टीचर और बहुत से वाइस चांसलर भी शामिल हैं। वे सब इस तरह की बात चाहते हैं क्योंकि इस सरकार से उनको काफी तकलीफ है।

[श्री कंवर लाल गुप्त]

मैं चाहता हूं कि आप विद्यार्थियों को पुलिस की लाठी पर या वाइस चांसलर जो बायस्ड हैं उन के रहम पर न छोड़ें। उसके खिलाफ़ पुलिस की लाठी काम नहीं कर सकेगी। आपने एक सवाल के जवाब में कहा था जून 1977 में कि हम ने इंस्ट्रक्शंज जारी कर दिए हैं यूनिवर्सिटीज को और स्टेट गवर्नमेण्ट्स को भी कि जो विद्यार्थियों के ग्रीवेंसिस हैं उनको हल करने के लिए उनके साथ मिल कर एक कमेटी बनाई जाए और उनके ग्रीवेंसिस को दूर किया जाए और कोशिश की जाए ताकि उनको तसल्ली हो। इन इंस्ट्रक्शंज का कितना एम्प्लीमेंटेशन हुआ है? दिल्ली, बनारस, अलीगढ़ में क्या इम्प्लीमेण्ट किया है आपने? स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो किया ही नहीं है, यह मुझे मालूम है। यहीं कुछ नहीं हुआ तो वहां क्या हो सकता था। मैं जानता हूं कि जब कभी किसी वाइस चांसलर ने बात की है तो केवल रात के साथ की है, बराबरी की हैसियत उनको दे कर बात नहीं की है। केवल इंस्ट्रक्शंज इशू कर देने से काम नहीं होगा। अगर वे इनको इम्प्लेमेंट नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? यह कहेंगे कि आटोनोमस हैं?

Is it the only reply that it concerns the State Governments? Are you here only to look after the Ministry of Education? They have been given crores of rupees. You cannot take the plea that it is an autonomous board or a university and you cannot interfere in their affairs. Nobody can take this plea. You should not be a passive spectator and a most ineffective person. You must be effective and you must see that action is taken against those who indulge in illegal activities.

अगर ऐसा नहीं होगा तो कभी मामला ठीक नहीं होगा। कभी भी लाठी गोली से काम नहीं चल सकता है। पिछली सरकार ने सब स्टूडेंट कमेटीज तोड़ दी थीं। तब तानाशाही थी। आप तो इनको बनाएं।

दिल्ली का एक प्राबलम मैं बताता हूं। मैंने दिल्ली में होस्टल एकमोडेशन के बारे में सवाल पूछा था और आपने उत्तर में बताया था कि आपके हिसाब से होस्टल एकमोडेशन जितनी चाहिए उसकी पंद्रह परसेंट भी नहीं है। किताबें नहीं हैं, होस्टल एकमोडेशन नहीं है। टीचर्स की कहानी अपनी अलग ही कहानी कहती है। पचास परसेंट जिन के मार्क्स थे या जो थर्ड क्लास थे उनको रख लिया गया है और जो पी०एच०डी० थे उनको नहीं रखा गया है। पोलिटिकल प्रेशर में आ कर उनको भर्ती कर लिया गया, इनकम्पीटेंट टीचर्स को भर्ती कर लिया गया। नुरूलहसन साहब मिनिस्टर भी रहे और प्रोफेसर भी बन गए। एक मि० निगम हैं। वह प्रोफेसर भी बन गए हैं, और भी कुछ बन गए हैं। कोई आथटी-रिटी नहीं है। कह दिया जाता है सिलेक्शन बोर्ड है, हम क्या कर सकते हैं। अब अगर सिलेक्शन ही गलत किया गया है तो क्या किया जा सकता है? इनकम्पीटेंट टीचर्स हैं। आपने यह भी कहा है कि किताबें नहीं हैं। होस्टल एकमोडेशन की कमी है। सारे कालेज ओवर क्राउडिड हैं। एक-एक कालेज में दो, ढाई हजार बच्चे हैं जिसकी वजह से कोई रैपर्ट विद्यार्थियों और टीचर्स के बीच में नहीं रह गया है। तो नतीजा यही होगा। मैं चाहूंगा सरकार इस बारे में निर्णय ले कि हायर ऐजूकेशन सब के लिए है या कुछ लोगों के लिए है? हायर एजूकेशन किस हद तक सब के लिए करनी है और किस हद तक सब के लिए नहीं करनी है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वह मेन्टेन होनी चाहिए और उस हिसाब से सब चीज की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके बारे में कोई पौलिसी सरकार को बनानी चाहिए।

एक चीज और चाहूंगा कि जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं उनकी आप मीटिंग बुलाइये। अब एक साल से चर्चा चल रही है, मंत्री जी ने भी कहा कि बुलायेंगे। एक साल तो ऐसे ही चला गया, जिसका परिणाम यह है कि समस्या और भयानक होती जा रही है। अब चीज एक वोल्कैनों पर रखी हुई है जो कभी भी फट सकता है तो उसमें एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि आपने कुछ वाइस-चांसलर्स को बुलाया है लेकिन वह तो कुछ इधर कमिटेड हैं, कुछ उधर कमिटेड हैं। लेकिन आपको पोलिटिकल पार्टीज की मीटिंग जल्दी बुलानी चाहिए और कोड आफ़ कंडक्ट तय होना चाहिए, और सबसे पहले यह होना चाहिए कि मांगें कितनी भी जायज हों लेकिन हम वायलेंस नहीं करेंगे, और इसको सब मानेंगे। और उसके साथ-साथ जो बच्चों की, कर्मचारियों की, टीचर्स की दिक्कतें हैं उसके लिए कोई मशीनरी बनानी चाहिए जो वाइस-चांसलर से इंडिपेण्डेंट मशीनरी हो, और वहां पर जो निर्णय हो वह फ़ाइनल माना जाय। और जब तक पोलिटिकल पार्टीज का ऐक्सप्लायटेशन नहीं रुकेगा तब तक शांति नहीं होगी।

मैं चाहूंगा कि 10 प्लस 2 प्लस 3 का भी मामला साफ हो जाय कि आपकी पौलिसी क्या है? क्या चाहते हैं आप कि हर एक स्टेट में अलग-अलग सिस्टम होगा? मेरी राय है कि शिक्षा कानकरेंट विषय होना चाहिए, स्टेट सबजेक्ट नहीं होना चाहिए। जब तक शिक्षा ठीक नहीं होगी देश में प्रगति नहीं हो सकती। तो मेरी मांग है कि इस ऐजूकेशन को कानकरेंट सबजेक्ट करना चाहिए और सरकार राज्यों को गाइडलाइन्स दे जिसके आधार पर देश की इंटेगरिटी और डेमोक्रेसी बनी रहे और चरित्र का निर्माण हो, एक ऐकेडेमिक ऐटमास्फ़ीयर यूनिवर्सिटी में रहे। यह सरकार को देखना चाहिए।

श्री एच० एल० पटवारी (मंगलदाई): किसी के दिमाग में नहीं आता है।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): पार्टी का डिसीजन है।

श्री एच० एल० पटवारी : पार्टी का डिसीजन नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : एक चीज जो मैं चाहूंगा मंत्री महोदय क्योंकि स्वयं प्रोफेसर हैं, वह सब चीजों को समझते हैं और मैं यह मानकर चलता हूं कि उनको मेरे से ज्यादा ज्ञान है शिक्षा के बारे में, सारे जीवन का अनुभव उनके पास है, तो क्या बदल आप करना चाहते हैं ऐजूकेशन में, वह जल्दी से जल्दी क्यों नहीं करते हैं। आपको करना चाहिए ताकि ऐजूकेशन परपजफुल और मीनिंगफुल हो और बच्चों में विद्यार्थियों में विश्वास आये। जिस तरह ये तेरह महीने निकल गये हैं, उसी तरह पांच साल भी निकल जायेंगे। पिछली सरकार और हम सब लोग यह रागिनी अलापते रहे हैं कि ऐजुकेशन को बदलना चाहिए। इस को कौन बदलेगा ? मुश्किल यह है कि स्वयं डा० चन्द्र ने कहा है कि एजूकेशन बदलनी चाहिए। लेकिन वह बदलेगा कौन ? क्या मैं बदलूंगा, या ये माननीय सदस्य बदलेंगे या सभापति महोदय, आप बदलेंगे ? इसको तो मंत्री महोदय ही बदलेंगे। तो फिर वह क्यों नहीं बदलते ? इन तेरह महीनों में उन्होंने शुरुआत क्यों नहीं की ? इस बारे में डायलाग और डिसकशन होनी चाहिए और उस के बाद फ़ैसलों को लागू करना चाहिए। इस के लिए एजूकेशन को कानकरन्ट लिस्ट में रखना जरूरी है।

मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह कुछ ज्यादा इफ़ेक्टिव हों और थोड़ा ज्यादा एसर्ट करें। वह बहुत ज्यादा सीधे हैं। ये बातें कहते हुए मेरे मन को दुख हो रहा है; मुझे खुशी नहीं हो रही है। मंत्री महोदय को यह देखना चाहिए कि जहां जिस की ग़लती हो, उस को ठीक किया जाये। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर विचार करेंगे और एक सप्ताह के अन्दर अन्दर इस बारे में कोई कार्यवाही करेंगे।

दिल्ली में जिन लड़कों को रस्टीकेट किया गया था, और जब सारा एविडेंस कोर्ट के सामने रखा गया, तो कोर्ट ने उन्हें एग्जामिनेशन में बैठने की इजाजत दे दी और यूनिवर्सिटी को नोटिस दे दिया। क्या हमें बच्चों को कोर्ट में जाने के लिए मजबूर करना चाहिए ? तो फिर हम लोग किस लिए हैं ? ऐसा नहीं होना चाहिए।

एक दुर्भाग्य की बात यह भी है कि इमर्जेंसी के दिनों में जो लोग खुशामदी थे, वे आज भी खुशामदी बने हुए हैं। बटरिंग करने में वे पहले के एक्सपर्ट हैं। वे पहले उधर भी बटरिंग करते थे और अब उन्होंने इधर भी करना शुरू कर दिया है। परिणाम यह हुआ है कि हम जो कदम उठाना चाहते हैं, हम नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उन के भी हिमायती हैं—हमारी ही पार्टी में उन के हिमायती मिल जाते हैं। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति उन की पीठ पर हैं, इस लिए उनके खिलाफ़ कुछ नहीं हो सकता है। यह स्थिति सब यूनिवर्सिटी में है और यह खत्म होनी चाहिए।

प्रधान मंत्री को भी इस बारे में एडमिनिस्ट्री सुपुर्द किये हुए कई महीने हो गये हैं। प्रधान मंत्री जी से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह इतनी जल्दी इस काम को खत्म कर दें, क्योंकि उन को सारे देश का काम देखना होता है और उन पर बहुत भार है। इस लिए मैं यह नहीं कह सकता हूं कि उनकी कोई कमी है। लेकिन जितनी देरी होती जायेगी, उतनी ही यह खाई और बढ़ती जायेगी।

इस लिए मंत्री महोदय इन सब बातों पर विचार करें, वह एक यूनिवर्सिटी के बारे में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें, वह ज्यादा इफ़ेक्टिव हों, वह पैसिव स्पेक्टेटर न रहें और इस मामले में सिर्फ़ पुलिस की लाठी पर डिपेंड न करें।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That this House expresses its concern at the growing student unrest in universities and other institutions for higher education deemed to be universities and recommends to the Government to take appropriate steps to remove the causes of unrest."

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): I want to know what is the time fixed for the debate?

MR. CHAIRMAN: Four hours.

DR. RAMJI SINGH: (Bhagalpur): I beg to move:

That in the motion,—

add at the end—

"by providing relevant education and training in head, hand and heart; medium of instruction through mother tongue; providing stress upon Indian culture; providing common school and abolishing Public Schools; by abolishing compulsory membership of students union; introducing at least 2 months social work every year curtailing vacancies; delinking examination with educational curriculum, delinking examination with degrees and degrees with jobs and introducing moral and spiritual instructions in educational institution." (1).

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV (Saharsa): I beg to move:

That in the motion,—

add at the end—

"so that peaceful atmosphere is created in schools, colleges and universities and the students may feel that after passing out of universities their livelihood and future is secure." (2)

SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV: I beg to move:

That in the motion,—

add at the end—

"and in view of the fact that the present system and management of education as well as outlook thereon are responsible for this situation, further recommends that a high level Committee be constituted which may convene a national convention of educationists and social workers and in consultation with them, suggest radical changes and submit its report to the House within six months so that a decision could be taken thereon without delay and the House also condemns those who instigate the students out of political motivation." (4)

SHRI A. K. ROY: I beg to move:

That in the motion,—

add at the end—

"by ending the monopoly of upper classes in the higher education; enforcing reservation for the productive classes in the academic sphere and substituting production oriented education and society oriented culture to the present sterile decadent one carrying the stamp of colonial past." (6)

SHRI ANANT DAVE (Kutch): I beg to move:

That in the motion,—

add at the end—

"by providing such education as they should feel that they are the true architects of this country and after finishing their education they would certainly get jobs." (7)

SHRI YUVRAJ (Katihar): I beg to move:

That in the motion,—

after "and recommends to the Government to"

insert "make radical changes in the system of education and make it job-oriented and" (8)

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: (Cannanore): Sir, we are discussing a very important subject. The result of the discussions, I am sure, will be watched with keen interest by the entire student community in the country as well as the other sections of people of our democratic country.

Sir, while moving this Resolution my friend, Shri Kanwar Lal Gupta placed many important points before us. With some I may not agree; with a few I might agree with him.

But, I must say at the outset that the problem of student unrest should be viewed from a different angle than that which has been posed by Shri Kanwar Lal Gupta.

The student reflects the social unrest in the society in which we are living.

If a society is relatively calm and if they move forward smoothly and if the policies of the Government—whichever party is in power—give relative satisfaction to the younger generation then, in that society, there will be little scope of student unrest.

If a society is in turmoil and in revolt then I cannot expect the student community to be submissive. Especially the mood of the students who are in the universities will not reflect the mood which is existing in the society

So, I approach this problem from this angle. I am sure many of my friends sitting on that side will also agree with me on this point.

In this country—and for that matter, in the entire world—we can see the phenomenon of revolt on the part of the younger generation whenever they are dissatisfied and discontented with vital issues which concern the nation.

In our country during our freedom struggle the student community responded magnificently and they took part in every freedom struggle that we waged. They were the most effective instruments in carrying forward the freedom struggle. But soon after independence we found that the phenomenon of student unrest was coming more and more to the forefront. It is not something happening in the recent period alone.

What has happened? Without going into the details one can say this. There is a big gap between promises and performance. The gap is widening. There were promises about a new life in Independent India: promises about economic reform; promises about democratic rights, promises about a better system of education, promises of an education which will make them more useful citizen in their life later, all these promises were belied. As problems grew up, they started revolting against this system, against the whole attitude of the society towards them. And then perhaps Mr. Kanwar Lal Gupta will agree with me on one point, that is, when people come to power as you have now come to power, that is, your party, an attitude will develop, the attitude of sermonising the students saying "don't misbehave, be disciplined and we will do everything good for you." But that will not be enough and that will not be sufficient. The point is that there were people sermonising the students on that side when you were all along sitting on this side and we are hearing a little bit of sermons from you now.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I have not given any sermon.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: You did not try to do that. Now, let us go to the basic problem which the student community is facing today. Let us be sympathetic to them. I do not say that you are not sympathetic to them. The problem of unemployment is one of the most acute problems among the younger generation. The Janata Government made a promise and the Prime Minister had mentioned—you also made a suggestion—that in ten years the problem of unemployment would be wiped out. But what are the instructions through which you are going to implement those promises. I am not going to make it a debate on the problem of unemployment. The result has shown in one year's time, as it was revealed in the Economic Survey—Shri Kanwarlal Gupta wanted year to year programme and here is the year to year programme presented by your Government in the Economic Survey of India —that there will be 12 per cent increase in one year. 12 per cent increase of unemployment in one year will be there and your promise is that in ten years you are going to wipe out the problem. Who will believe that? In the next year, it is going to increase. There is no doubt about it.

Then, Sir, there will be revolt. Another problem which I do not want to refer here just now but I would mention about it that when you were speaking, I think there was a slogan shouting outside and there was hushing up also. The students of Kanpur came here to say that their Vice-Chancellor should behave properly. The problem which you raised, of shouting and killing is no remedy, arrest is no remedy to the problems of the students. They came here to tell us about the problems on the day when Shri Kanwarlal Gupta, one of the leading luminaries of the Janata Party, was raising a discussion on this subject. But what is the reply the

[Shri C. K. Chandrappan]

Minister is going to give today? The condition in our country is that almost in the entire North Indian States where the Janata Party swept the polls, the educational institutions, the higher educational institutions have come to a state of an absolute paralytic situation. It is not a very enviable thing. You cannot deal with these problems merely as a law and order problem. There, you have dealt with the question of educational reform and the democratic rights of the students. When coming to the problem of educational reforms, one of the most menacing problems is the problem of examination. I have been going through the reports of most of the students agitation these days; the students find question papers very tough and they refuse to answer them; you bring police to make them answer the tough questions; they find that the invigilators are misbehaving or they have complaints, genuine or not. Anyway examination reform is a matter of urgent importance. I know the government will say : we have appointed so many committees and they have made so many recommendations and we are trying to implement them. But that is no solution. In the last thirty years the country was hearing all this but not much appreciable change in the basic character of the examination system in our country has been made during this period by any recommendation. Let us take the students into confidence; sometimes it is good. Let us have a meeting of the students, teachers and people who are interested in education, educationists; let them discuss how this problem of education reform, particularly the problem of examination reform can be solved. The solutions which they suggest might be better than the suggestions of so many experts who may have very little relation with the student community. I hope such a step will be taken by the government.

Coming to the text book problem, which Mr. Kanwarlal Gupta raised, it is not merely a question of text books not being distributed. What are the contents of those text books. The contents in many cases are unrelated to Indian lives and the students find it extremely boring to read about things that have no relevance in today's society or to our country. So the content should be made something which is related to his life, something which will be useful to him as a citizen of this country, something which will uphold national traditions as well as national goals the country pursues. I will say that Marxism should be made a subject for students to learn; I do not know whether Mr. Kanwarlal Gupta will agree to that. When you speak of socialism, Marxian socialism should be taught; it is essential. The idea of secularism should be put across and the students should learn in an atmosphere of secularism. The idea of democracy should be practised, not only preached; it should be practised in the university campus by giving them the right to form students' union and giving them the right to have adequate participation in the administration of academic matters of the university. There should be democratic functioning of students unions. It should be statutorily ensured in all the universities and colleges and that should become a forum for the entire student community of India to express their problems, not only for expressing their problems but to participate in creative, constructive activities! there should be adequate student participation in the administration and academic matters. I must even say that even in the framing of questions for examinations, student participation is good. It is my view. In the examination halls, open text book policies should be adopted.

Another important problem is about the teacher. Mr. Gupta said that the teacher was not studying enough to teach the student community. I may also agree that he is not studying properly. Then what about his living

conditions? Do we take care to see the condition in which the teacher is living? It is good that the hon. Minister of Education is coming from West Bengal. I will draw his attention to the famous film directed by Satyajit Ray, *Janaranja* in which you find the example of a Calcutta teacher and how he values examination papers, under what conditions and with what result. He is using a kerosene lamp almost flickering out and mosquitoes are coming. The teacher is not having a proper spectacle to look at the paper; because that is an old one, he is searching for a friend's speaks and the friend has gone to Calcutta and the teacher has to evaluate the paper the same night and he did it without seeing the paper and the result was, he created some frustration in the minds of the students. Therefore, the living condition of the teachers should be improved.

Finally about violence and the role of the political parties, to which Mr. Kanwar Lal Gupta referred in his speech, I am in full agreement with him when he says that the students should not indulge in violence. But I must make an appeal to the ruling party, because they are more responsible for that, that they should create such a condition in the country that the students will not indulge in violence. If you send police vans to the Universities often and if you try to find solution with an iron-hand to their genuine problems, then violence will be there because it will be retaliated in the same fashion by the student community. After all, you should not forget the fact that you are dealing with the younger people, inflammale material. You should be very careful, very sympathetic and very tactful in dealing with them. If that situation is created, there will be little scope for violence.

About the Emergency. If you think that the student community is revolting because the Government is not taking those measures of democratisation in the Universities in tune with what has happened in the last Election, I may disagree with that. I do not think that that is the main thing. That may be one of the smaller problems in their minds. The main thing is that the student community is seeing another failure in place of the Congress failure.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: That is not the main thing. You do not understand it because you have not suffered. Those who have suffered can understand it.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: I do not know whether you suffered or I suffered.

If that was true, in the recent election in the Northern Indian Universities, Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad, whose suffering is known to Mr. Kanwar Lal Gupta, would not have faced such a total reverse, it faced. That is not the problem. Those who championed the struggle in those days were rejected by the student community because in the minds of the student community, expectations were roused in the name of total revolution, speaking against corruption, promising new values, new life, but they do not find that that is being practised. So, they find that whereas the Congress failed during the last thirty years, the Janata Party in the thirteen months has presented the same dismal picture of failure. If that picture of failure is further presented there will be further revolt and unrest among the student community. There is no point in finding *alibi* that Congress is creating. Congress is not that powerful to create that; it is not that when they switch on, the students revolt. No. If you succeed in solving their problems, in reforming education, in promising them employment, a democratic atmosphere in the Universities, academic freedom, right of participation and democratic rights, I am sure that you will succeed in creating an atmosphere, where there will not be student unrest. Your failure is rather faster than that of the Congress and that is why I think there is

[Shri C. K. Chandrappan]

student unrest. I hope the Janata Party will take sufficient attention from the experience of the last thirteen months to solve those problems and that will bring credit to them.

With these words, I conclude. Thank you.

सभापति महोदय : आप केवल दस मिनट में । बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । मुझे घंटी बजाने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिये ।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : छात्र असन्तोष का विषय पुराना भी है और साथ साथ महत्वपूर्ण भी । इतने थोड़े समय में इस पर विस्तार से प्रकाश डालना मुश्किल है । छात्रों का असन्तोष केवल भारत में ही ऐसी बात नहीं है । यूनान में भी प्राचीन समय से यह था । सुकरात ने भी कहा है कि ऐसे छात्र थे जो उपद्रव किया करते थे । वाल्मीकी रामायण में भी लिखा गया है कि कई प्रकार के छात्र थे जो बराबर उपद्रव करते थे, जो इस आश्रम से उस आश्रम जाया करते थे । पाणिनि ने अपने महा भाष्य में उपद्रवी और अशिष्ट छात्रों की चर्चा की है । हमारे समय में छात्रों में असन्तोष का आयाम खास कर 1950 से उभरा है । तब यह असन्तोष छुटपुट था । 1960 से 1970 तक यह बहुत ज्यादा हो गया । छात्र जगत और खास कर उच्च शिक्षा जगत में यह असन्तोष तीव्र है । इसके सम्बन्ध में बहुत सी गवेषणायें भी हुई हैं, बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई हैं । शिक्षा के सलाहकार प्रो० हुमायून् कबिर साहब ने भी इस पर विचार विमर्श किया था, स्टूडेंट अनरेस्ट काजिज एंड क्योर 1958 । चंचल सरकार ने Unique Campus 1968. / एस एस सिन्हा साहब ने 1962 में,
The Problem of Student Unrest.
यू.जी.सी. में भी इसके सम्बन्ध में 1960 में विचार किया / यूनियन मिनिस्ट्री ने'
Depth Study Student Strikes 1958 –64
वर्ल्ड अदरहुड ने भी
Understanding Students 1960
इस तरह से और ज्यादा विस्तार में जा कर मैं आपका समय लेना नहीं चाहता हूं । इस असन्तोष के कारणों और उसके समाधान बताने के लिए कई समितियां नियुक्त हुई और पुस्तकें लिखी गई । अब उस सब की चर्चा करना बेकार है ।

परसों छात्र असन्तोष पर इंटरव्यू लेने के लिए एक हिन्दी पत्रिका वाले मेरे पास आए थे । उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि राष्ट्रपति जी से ले कर एक सामान्य व्यक्ति भी कहता है कि छात्र असन्तोष वस्तुतः कोई बीमारी नहीं बीमारी का वस्तुतः लक्षण है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश की शिक्षा पद्धति ऐसी जीर्ण शीर्ण हो—जैसी हमारे देश की है उस देश में शिक्षा के क्षेत्र में असन्तोष होना स्वाभाविक है । हम जड़ को नहीं पकड़ते हैं और यही कारण है कि छात्रों में देश में असन्तोष है । वैसा मैंने आप से कहा, कि सब लोग केवल उसका चीरी इलाज ढूंढना चाहते हैं सी आर पी, भी एस एफ को भेज दिया जाता है । कुछ वाइस चांसलर्ज की बात भी मेरे मित्र ने कही है । लेकिन ये सब केवल ऊपर की बातें हैं । जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा । वर्तमान शिक्षा पद्धति न जीवन देती है और न ही जीविका की गारंटी । जिस शिक्षा से मनुष्य को कोई प्रेरणा नहीं मिलती उस शिक्षा में असन्तोष का फैलना स्वाभाविक है ।

मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं । मैं एक डिग्री कालेज के प्रिंसिपल की इंटरव्यू में गया । वहां मुझ से पूछा गया यही प्रश्न कि

What is the cause of student indisiciplne?

छात्रों में अनुशासनहीनता का कारण क्या है । मैंने कहा कि छात्र अनुशासनहीन नहीं हैं । इस पर उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं अनुशासनहीन नहीं हैं ? मैंने बहुत विनम्रता से तब जो कुछ कहा वही मैं अब आपके सामने दोहरा देना चाहता हूं । मैंने कहा था:

When officials are corrupt, politicians bankrupt, businessmen cheats, lawyers frauds and we, the teachers, a band of professional wage-earners. How can we expect our students to be disiciplined? They are more disiciplined than they ought to be.

वस्तुतः जिस देश का राजनीतिज्ञ इतना अनुशासनहीन हो कि नामांकन भरता हो राष्ट्रपति पद के लिए किसी का और वोट देता हो दूसरे को । जिस देश के राजनीतिज्ञ, हम अपने को भी उसमें शामिल करते हैं, जो घोषणा-पत्र के वायदों को भी निभायेंगे, उसमें भी संकोच करते हैं, जब सारे जगत में अनुशासनहीनता है वहां छात्रों से कहें कि अनुशासन में रहें, यह कभी नहीं हो सकता । मैं चन्नप्पन जी से सहमत हूं कि छात्रों का असंतोष केवल शिक्षक जगत के ही कारण नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक और आर्थिक परिवेश के कारण है । मैं शिक्षा मंत्री जी के प्रति आदर रखते हुए भी जो कभी कभी पदायन करते हैं और कह देते हैं कि यह मेरा काम नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवेश का है, जब तक वह नहीं बदलेगा तब तक काम नहीं चलेगा, यह कह कर आप अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते । आपको देखना होगा सचमुच में शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं करते हैं तो केवल सामाजिक, आर्थिक पद्धति को दोष देने से काम नहीं चलेगा । इसीलिये एक तरफ अगर हम शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें साथ साथ समाज में भी परिवर्तन करना होगा । इसीलिये दोनों में करना होगा । लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा दोष है शिक्षा पद्धति में परिवर्तन का । अब हम दिशाहीन नहीं हैं, गतिहीन हैं । जनता पार्टी की सरकार में दिशा की कमी नहीं है, गति की कमी है । मालूम होना चाहिये छात्रों का असंतोष आपातकालीन लौह दंड से जो दबा दिया गया था वह उभरा है और जनता

पार्टी की सरकार से जो नवयुवकों को आकांक्षायें थीं अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उनका असंतोष बिखरेगा और इसका कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिये आवश्यकता है जो काम कांग्रेस सरकार 30 साल में नहीं कर सकी उसको हम लोग 4, 5 वर्ष में करें। डेढ़ वर्ष हो गया अभी हमने 10 प्लस 2 प्लस 3 का श्राद्ध नहीं किया। छोड़िये हिन्दी और अंग्रेजी का प्रश्न। लेकिन शिक्षा के सम्बन्ध में शैक्षिक दृष्टिकोण से शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिये। यह भी अभी तक समूचे देश में नहीं हुआ है। इसीलिए बिहार में अगर लोग कहते हैं कि हिन्दी में पढ़ेंगे तो लोगों को एतराज हो जाता है। हम कहते हैं कि हिसाब का माध्यम हिन्दी होना चाहिये, जिनकी मातृभाषा तमिल है वह तमिल में पढ़ें। इसलिये एक प्रश्न तो सामाजिक परिवर्तन का है, दूसरा शिक्षा पद्धति में परिवर्तन का है और तीसरा एक चीज हमारे पुराणों में लिखा है कि यदि छात्र असंतुष्ट होता है तो उसका बहुत सा भाग शिक्षक पर होता है।

शिष्यापराधे, गुरुर दंड : जिस देश का शिक्षक घटिया दर्जे का राजनीतिज्ञ होगा उससे शिक्षा की की क्या आशा हो सकती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे उनको चावल पीस कर दुग्ध के रूप में दिया जाता था "वत्स इदम् दुग्धम" तब उसके लिये एकलव्य अंगूठा दे सकता है। आज तो विद्यार्थी हम ही को अंगूठा दिखा देंगे। इसलिये शिक्षक के चरित्र निर्माण का मुख्य प्रश्न है।

छात्र असंतोष के सम्बन्ध में एक और भी बात है और वह है हमारे और विद्यार्थियों के बीच जैनरेशन गैप। हमारा मानस कुछ है और बच्चों का मानस कुछ है। इसलिये जब तक जैनरेशन गैप को समाप्त नहीं करते हैं उनकी मनोभावना को हम नहीं समझेंगे तब तक हम उनको दिशा भी नहीं दे सकते हैं। आज राजनीति से छात्र नीति का अलगाव हो गया है और यही कारण है असंतोष की ज्वाला कभी भी फूट पड़ती है।

अब मैं शिक्षा मंत्री जी के सामने दो, तीन रचनात्मक सुझाव रखना चाहता हूं। शिक्षा की समस्या के समाधान के लिए साहस भी चाहिए और कल्पना भी चाहिए। अगर माओ-त्से तुंग ने चीन में शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया, तो हाफ वर्क और हाफ एजूकेशन की बात कही। माननीय सदस्य, श्री चन्द्रप्पन, ने रूस की बात कही है। रूस में मेकेन्को ने कहा कि एजूकेशन में डिग्निटी आफ वर्क का समावेश करो। कोठारी कमीशन ने वर्क एक्सपीरियंस की बात कही है। मान्टेसरी ने एजूकेशन थ्रू वर्क की ओर डिवी ने भी वर्क एक्स-पीरियंसों की बात कही। अगर हम उस को लागू नहीं कर सकते, तो जिस तरह से आज हम केवल ऐकेडेमिक शिक्षा दे रहे हैं, उस का परिणाम एम्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशाप के रूप में ही प्रकट होगा।

शिक्षा में परिवर्तन के लिए तीन बातें आवश्यक हैं: मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, शिक्षा हमारे सांस्कृतिक परिवेश में होनी चाहिए और शिक्षा में ज्ञान और कर्म का समन्वय होना चाहिए।

मैं ने अभी हाल ही में कहा था कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जो असंतोष है, उस को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री को तात्कालिक कदम उठाने चाहिए। अगर तात्कालिक कदम नहीं उठाये जायेंगे, तो बहुत कठिनाई होगी। इस बारे में राजनैतिक दलों को भी सहयोग करना चाहिए। आज तो विद्यार्थी और मजदूर राजनीति के दो उपकरण हैं। हर राजनैतिक पार्टी का विद्यार्थियों का भी फ्रंट है और मजदूरों का भी फ्रंट है।

पहले हिन्दुस्तान में 400 कालेज थे, जबकि आज 4,000 कालेज हैं। आज हमारे देश में 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। शिक्षा का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि अगर इस सम्बन्ध में तत्काल कोई पग नहीं उठाये जायेंगे, तो छात्रों का असंतोष और अधिक भड़केगा। आज उन के लिए शिक्षा का अर्थ है निराशा, शिक्षा का अर्थ है हताशा। इस लिए जब तक शिक्षा सार्थक नहीं होगी, रेलिवेंट एजूकेशन नहीं होगी, परपजफुल एजूकेशन नहीं होगी, तब तक उनका असंतोष बढ़ता रहेगा।

इस लिए मैं शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि वह देश के सभी राजनैतिक दलों को बुला लें, सभी छात्र नेताओं को बुला लें, और उनसे कहें कि राजनीति के जो प्रश्न हैं, वे उन पर राजनैतिक ढंग से लड़ें, लेकिन शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, को वे चलने दें। शिक्षा में सम्बन्धित सभी मुद्दों पर विस्तार से विचार किया जाये। जब तक हर एक विश्वविद्यालय में इस प्रकार की चर्चा नहीं होगी, तब तक सी.आर.पी. के बल पर छात्रों का असंतोष कम नहीं किया जा सकेगा, जैसे कि वह पहले भी कम नहीं किया जा सका है।

श्री एच. एल. पटवारी (मंगलदाई) : सभापति महोदय, मैं अपने मित्र, श्री कंवर लाल गुप्त की भावना का स्वागत करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। कोठारी कमीशन ने कहा है कि बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना सरकार का अधिकार नहीं है। तीस साल तक यह निर्णय नहीं हो पाया है कि हमारे देश में क्या शिक्षा होगी, कैसी शिक्षा होगी। बच्चों की शिक्षा के बारे में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। वह सरकार का अधिकार नहीं है। शिक्षा मंत्री स्थिर और तरीके से निर्णय कर के देश को बता दें कि हमारी शिक्षा ऐसी होगी।

सारे देश की जनता ने यह फैसला कर लिया है कि शिक्षा भारत सरकार की जिम्मेवारी होगी। हिन्दुस्तान में शिक्षा कभी भी राज्य का विषय नहीं था, पुराने काल में भी नहीं था।

[श्री एच० एल० पटवारी]

राजा लोग अपना राज चलाते थे, लेकिन शिक्षा कभी भी राज्य का विषय नहीं था। किसी कारण से कांग्रेस शासकों ने इसको राज्य का विषय रखा जिसके परिणामस्वरूप देश में इसका तीव्र विरोध हुआ, देश में असंतोष फैला, इसके लिए आंदोलन हुए, सारे देश के लोगों ने भारत सरकार पर दबाव डाला, सारे देश के प्राथमिक अध्यापकों ने भारत सरकार पर दबाव डाला तब भारत सरकार इसको कानकरेंट लिस्ट में लाई लेकिन फिर भी सेण्ट्रल लिस्ट में नहीं लाई। हमारे शिक्षा मंत्री जी पार्टी के डिसीजन के नाम पर इसको पुनः स्टेट्स को देना चाहते हैं—मुझे इस बात का बड़ा दुःख है। आज शिक्षा मंत्री कैसे कह सकते हैं कि यह पार्टी का निर्णय है? पार्टी का निर्णय है कि शिक्षा को कानकरेन्ट लिस्ट में रखा जाये। स्टैंडिंग कमेटी आन एजूकेशन ने निर्णय लिया है, सारे मेम्बर्स ने अपनी भावना व्यक्त की है और कंसल्टेटिव कमेटी ने भी निर्णय लिया है, उसके सारे मेम्बर्स ने अपनी भावना व्यक्त की है कि शिक्षा कानकरेण्ट लिस्ट में रहनी चाहिए। फिर आप क्यों कहते हैं कि पार्टी का डिसीजन है? आप पार्टी को क्यों बदनाम करते हैं। इससे सारे देश के अध्यापकों में असंतोष पैदा हुआ है। पार्टी का ऐसा निर्णय कभी नहीं है। हम इसका घोर विरोध करेंगे। अगर इसके लिए संविधान संशोधन आयेगा तो मैं कहता हूं कि हम इसका काम रोक देंगे, हम उसको कभी भी पास नहीं होने दगे। चाहें हमारी जान चली जाये लेकिन हम कभी भी शिक्षा को कानकरेण्ट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में नहीं जाने देंगे। कोई भी इसको लायेगा, हम उसका घोर विरोध करेंगे, हमारी पार्टी के मेम्बर्स इसका विरोध करेंगे। भीतर और बाहर सभी जगह इसका विरोध किया जायेगा। चाहे कुछ भी हो हम सारे देश में घूम घूम कर कहेंगे कि शिक्षा कानकरेण्ट लिस्ट से नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि आप आइंदा कभी भी न कहें कि यह पार्टी का स्टैण्ड है कि शिक्षा कानकरेन्ट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में चली जाये। अगर मंत्री जी की ऐसी अपनी व्यक्तिगत भावना हो तो कोई बात नहीं है लेकिन उनको पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए। आज सारे देश के, अध्यापक जो कि जनता पार्टी के साथ थे, वे उससे अलग होते जा रहे हैं। इसी तरह से सारे स्टूडेण्ट्स जोकि जनता पार्टी के साथ थे वे भी अलग होते जा रहे हैं। क्योंकि हमारी कोई शिक्षा नीति है ही नहीं। मैं कहता हूं कि जनता पार्टी के 13 महीने के शासन में दस प्लस दो प्लस तीन के अलावा और कोई बात जनता ने नहीं सुनी। यह दस प्लस दो प्लस तीन क्या होता है, यह कोई भी नहीं बतला सकता। आज हिन्दुस्तान की जनता भारतीय शिक्षा चाहती है। हिन्दुस्तान की जनता ऐसी शिक्षा चाहती है जिससे कि देश में साम्यवादी समाज का निर्माण हो। अगर देश में साम्यवादी समाज का निर्माण होगा तो इस देश में पूंजीपतियों की दलाली नहीं चल सकेगी। आज हिन्दुस्तान की जनता चाहती है कि इस देश के सभी बच्चों को एक ही किस्म की शिक्षा प्राप्त हो।

मैं अभी राजस्थान गया था जहां पर मैंने देखा कि गांव के स्कूलों के लिए भवन नहीं हैं। उसके विपरीत आज दिल्ली में सवेरे मने एक स्कूल देखा जिसकी बिल्डिंग के लिए चार-पांच लाख रुपया दिया गया होगा। हमारे असम में जो गांवों के स्कूल हैं वहां पर मैंने देखा कि उसके सारे दरवाजे और खिड़कियां खुली रहती हैं। ऐसे स्कूल है जिनमें ऊपर से पानी गिरे। ऐसी खिड़कियां हैं कि किनारे से बैल अन्दर घुस जायें। और नीचे इतनी गन्दगी जिसका कोई हिसाब नहीं। कहने का मतलब यह कि जो भी सबसे खराब हालत में भवन दिखाई दे उसको समझ लेना चाहिए कि यह विद्यालय है। हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों के दिमाग में यह भावना नहीं रहनी चाहिए कि बिड़ला जैसे सेठों के यहां पेशाब करने की जगह बनवाने पर भी बीस हजार रुपए लगते हैं। और हमारे पढ़ने के लिए जो भवन हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है। जब बच्चे ऐसा देखेंगे तो कैसे उन के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कैसे उन के दिल-व-दिमाग में अच्छी भावना पैदा होगी कि हम स्ट्राइक न करें। वे नहीं चाहते हैं कि स्ट्राइक करें या इनडिस्प्लिण्ड बनें। लेकिन हिन्दुस्तान के बच्चों के दिल-व-दिमाग में यह भावना है कि हमारी जो आशायें थीं, वे पूरी नहीं हुई। उन आशाओं को पूरा करने के लिए हम ने क्या किया है? मैं तो यह देखता हूं कि उस के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है कि देश में क्या होना चाहिए। जब तक हम इस में कोई व्यवस्था नहीं करेंगे—मैं समझता हूं कि यह असंतोष इसी तरह से बना रहेगा और इस के परिणाम हम को आगे चल कर भुगताने होंगे।

अब मैं तीन-चार सुझाव देना चाहता हूं :—

(1) विद्यार्थियों में असंतोष का क्या कारण है? विभिन्न समयों पर जो कमेटियां बनी और उन्होंने जो सुझाव दिए—उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए—असंतोष के कारणों का निश्चय किया जाना चाहिए।

(2) बच्चों को उकसाने के लिए कौन-कौन से राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, वे रात और दिन में कब उन को उक्साते हैं — इस के लिए अनुसन्धान करना चाहिए।

(3) हिन्दुस्तान में शिक्षा व्यवस्था कर्म-केन्द्रित, ज्ञान-केन्द्रित, देश-प्रेम और समानता पर आधारित होनी चाहिए, इस का पाठ्यक्रम इन्हीं आधारों पर बनाया जाना चाहिए।

(4) हमारे गांव प्राथमिक शिक्षा और विश्व-विद्यालय की शिक्षा के बीच में लिंक रहने चाहिए। इस समय प्राथमिक स्कूल और विश्वविद्यालय के स्कूलों या कालिजों में कोई सामंजस्य नहीं है, इस लिए इन का लिंक होना चाहिए।

(5) विश्वविद्यालयों पर जितना खर्च होता है, उस से कहीं ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों पर खर्च होना चाहिए, ताकि जो नींव है, वह मजबूत हो सके।

इन शब्दों के साथ अन्त में मंत्री महोदय से एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। यदि किसी को कान्फरेन्ट लिस्ट से निकालने की आवश्यकता उनके दिल-व-दिमाग में हो, तो वे उस को निकाल दें। हम चाहते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची में रहे, यदि आप ने निकालने की कोशिश की तो हम इस का घोर विरोध करेंगे—इस बात को आप समझ लें।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): I have heard the contributions of many of our friends to the debate. I have to agree with Dr. Ramji Singh when he said that there is a huge difference between people who belong to the earlier age and the children and boys who belong to the atomic age. Our aspirations and our thinking are different from their aspirations and their thinking, and we are not able to understand them. That is one aspect.

The second aspect is that they cannot be different from us. When society is bristling with unrest, we cannot say that there will be rest amongst the students. When a student's father is without food, when his parents are undergoing difficulties, how can we thing that he can have peace? In an unsettled society, it is very difficult to think that there will be peace among the students. But I am very much astonished to see that this phenomenon is there not only in our country but it is prevalent everywhere. There are developing countries and developed countries. We see that there is unrest amongst the youth in the developed countries also. Therefore, we must give a thought as to why this unrest is there in countries where the social systems are different, economic systems are different and where disparities are there.

18 hrs.

Now, what we see here? We see that our boys are beating the Vice-Chancellors. Our boys are breaking the bones of their professors. They are breaking heads amongst themselves. In Triputi University, two groups of students broke their heads, fought amongst themselves. In Osmania University in Andhra Pradesh, one group stabbed one leader of the students. In Bihar, they fought among themselves and killed four or five. In North, there is fight amongst students. Why is it so? Our people have said that the unrest is more in the North. It is not so. Everywhere this unrest is there. Even in South, there is unrest. In South also, some of the universities have been closed down. Everywhere this unrest is there. Therefore, we cannot differentiate by saying that there is unrest in the North and no unrest in the South. It is the same everywhere. Our people have said that examination is the cause, absence of educational reform is the cause. But I see that elections are also the cause. We are conducting elections. We want democracy in our universities. I am not against it. But what is the result? Because of the elections in universities, communalism is coming to the forefront. Even those who have made social surveys have said that because of the elections in universities....

PROF. P. G. MAVALANKAR: This debate is meant for four hours. It should have started at 4 O' clock. But because of unavoidable and pressing matters, we started late. So, at least we should know as to how long it will continue. The other alternative is to carry forward this discussion to the next session.

MR. CHAIRMAN: We will sit upto 8.30 p.m.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Is that the decision of the House? Please take the opinion of the House. Otherwise, there will be difficulty.

MR. CHAIRMAN: Four hours were allotted to this and that would be over by 8.30.

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा): सभापति महोदय, हमारा प्रस्ताव है कि नेक्स्ट सेशन के लिए इस को कन्टीन्यू रखा जाए। साढ़े आठ बजे तक कोई बैठ नहीं सकता है।

सभापति महोदय: आप कृपा कर के बैठिये लोग बैठेंगे।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: I was speaking about elections. The hon. Minister must also find out whether the elections are not a cause for unrest. Specially, in Tirupathi University, in Andhra Pradesh, the elections are becoming a cause for quarrels amongst the students for unrest, for strikes and other things.

The problems of students are different from the issues which they are bringing forward. There may be some problems. They may say, "We are not having text-books; the syllabus is heavy; there are some difficulties with regard to hospitals", etc. But now the students are saying that the Vice-Chancellor must be dismissed; a professor must be transferred. Is it good? Can we allow that? Can we permit it? How to encounter that? These are the problems. Therefore, we must bifurcate the problems that we are facing into two parts, that is, the problems of students and the students who are taking up issues other than the problems of students.

With regard to the problems of students, certainly, the authorities, the universities and also the Government should take more interest and see that their problems are solved. If they want to dictate terms with regard to the posting of a Vice-Chancellor or the transfer of a professor, then, I think, it is beyond them.

Some people say that politicians are also playing. Yes, it is a fact. In some of the universities there are certain violent elements who are instigating the students for their own purposes. I am sorry to say that in the name of total revolution, in the name of utilising youth power, the students have been instigated in Bihar Is it not a fact that this unrest also is a result of that? Therefore, however great a person may be, he must not instigate the students. I understand that the students should understand politics because our life is not separated from politics. The student requires text-books; the student requires food and everything. Life is connected with politics. Therefore, he must understand politics. But is it necessary for him to involve himself in active politics? These are some of the problems

There are so many committees. They have given their impressions. The hon. Minister knows much more about these things because he is in touch with the problems. I have to say one thing that in one of the committee reports I have seen that because of the concentration of students in the colleges—thousands and thousands of students are concentrated there—there is no rapport between the teacher and the pupil. Therefore, I want to suggest to the hon. Minister in regard to having the structural change that instead of 10 plus 2 plus 3, just as in America, why not we have 8 plus 4 plus 2? Then, all the 12 classes can be in the villages and the concentration of students in the towns and cities can be lessened, the problems of students will be lessened and, therefore, we can solve the problems of students to a certain extent.

SHRI A. BALA PAJANOR (Pondicherry): Mr. Chairman. I thank you for giving me this opportunity to participate in the motion moved by the hon. Members Mr. Kanwar Lal Gupta and Mr. Chandrappan. But I am not one like Bernard Shaw to say that youth is based on the young and the pessimistic mood. I have always a feeling that youth is not properly utilized. But when I saw Dr. Chunder Sahib taking over the portfolio I had a great faith in him and thought that he would solve this problem because he belonged to a party that believed in the total revolution by great Loknaik. I am not going to describe the historical development of student unrest in this country as is done by Mr. Chandrappan and of course to a great extent by Mr. Kanwar Lal Gupta, because he spoke in an entirely different

language which I could not follow. But, anyway, I can understand the substance of it. I feel that student unrest has become a national phenomenon in this country. But it has become a fashion for us also to preach when we cease to be a student.

Last year, I had been to a college and I felt why I was not a student at that time and why I left that profession because we consider that the position of a student is also a profession. For some time, I felt happy because I had the experience of a teacher in a college also. Now I am a politician and being a Member of Parliament, I am talking from this big portfolio and discussing about student unrest in a very philosophical and moral attitude as if this class has failed to understand the moral values and the responsibility of it. As a Member, I also want to repeat what I said on the occasion of vote of thanks to the President's Address. I said: perhaps the generation gap is the main element and that is the reason why we are not able to understand the real reason behind this unrest. The generation gap is so much and the future is going so fast that we are not able to understand and appreciate these people and their aspirations. And very often, we politicians have been the cause to create this unrest not only in the past, not only in the present but we are also paving a ground for the future.

As far as unrest is concerned, I can classify this into two categories. The first category is the category of unrest due to political and personal reasons. The second category of unrest is due to national and greater causes. When Bapuji, our great freedom fighter, the Father of Nation, roused the student population to rise against the British riots, it could never be called a student unrest. I hope all of us will agree to that. In those days, the British people were preaching this kind of unrest among students as very bad for the nation. But I am sure this August House without any exception, will say that Bapuji was correct in saying that it was for the national cause or for the survival of this country that unrest was created in the minds of students and that was justiciable.

After that, after Independence, were also causes because during the time of Loknaik, there was a total revolution by the students. Of course, I never agree with the idea to ask the students to stay away from colleges for a year, to protest against that regime that was considered to be bad in those days and ask the students to keep away from examinations and all that. We never agreed to that, but it was in the name of the total revolution that the students were induced and unrest was there not only in the South, not only in the North but practically in the entire country. But I am not going to blame that inducement. But there is a subtle difference between the reasons that were given by Bapuji and the greater cause of this country's freedom. And subsequent to freedom, any unrest in the minds of the students, if it was created for any cause, I am not going to agree with that that it is the correct method of inducing the students. Perhaps we had inculated in the minds of the people of this country an idea that to revolt is the first aspiration or the show of valour or courage because we have seen, as I said in the beginning, that our national leaders are such as there is a generation gap. As a young student, when I was perhaps seven years or eight years old, I remember how Bapuji used to ask people to come out of the colleges and fight for the freedom of the country. Those people left the colleges and even today I see many people are.... I could have completed my college course and become the Professor of English but for the great call of Bapuji I could not become the Professor of English and so on. But this kind of continuation—I mean doing these things continuously—has been a credit to those people. So, such kind of mentality grew in this counry and even after Independence, such case was put before the students and those students were taken away by that. That is the

[Shri A. Bala Pajanor]

reason why I said, there is a generation gap between that generation and the present generation which wants to make use of the student population for the personal gains. When I say the personal gains, it is not to accumulate the wealth of fill the coffers with money bags but the personal gains of political survival in their own particular sphere. If it is a question of regional politics, they induce the students to regionalism. If it is a question of some fight between two rival groups in a particular State, they may induce the students. Just now it was said that some people were against the Chief Minister of U.P. and the students would have been induced. But I am not going to analyse the causes for this student unrest. But why this is existing in this country is the question. I believe that Dr. Chunder will analyse and understand in a better manner. Some solutions were given by some good speakers.

We find that there is a great difference or gap between teachers and students in this country today. I am sorry to make this remark.—I was one among the teachers for some time and was also a student for a long time. I do not blame the teaching class. It is not that all of them do not deserve to be in that position. Many reasons have been given by many hon. Members—because it is not lucrative or attractive, we have not been able to get proper personal. If you make an analysis, you will find that the teaching profession has become some sort of a stop-gap arrangement for a better profession. Many of these IFS and IAS officers were once lecturers in Colleges before they competed for the IFS and IAS examination. If they get better chances in life, naturally they get out of the teaching profession. In Russia, I am told, the teachers are paid the highest because they are the most respected there. In Tamil Nadu and, for that matter, all over the country, there used to be the proper relationship between the guru and *'Shishya'*. The guru used to be respected because he used to be the real guru those days, but now the guru is only a broker in this country; that is a very unfortunate aspect.

I am not going to refer to UGC or other matters. It is easy to criticise, but it is difficult to analyse and take correct and definite decisions. Taking definite decisions is also easy as far as we are concerned, but it is very difficult to execute them.

I thought that the Janata Government would go into this matter because they said that they were going to present a clean government. They told the students that it was because of corruption that they were not able to get jobs, it was because of corruption they were not able to get through their examinations, it was because of corruption in every nook and corner of the country that the student population was being put to this kind of malady; that was the main reason for the problem of unemployment which was growing from year to year to a gigantic size. They had said all this, but what has happened after they have come to power. Land Action said, 'Power corrupts and absolute power corrupts absolutely'. I do not say that the present Government is corrupt to the extent of absoluteness. But, in a way, there has been the element of tasting of power. This tasting of power has given rise to this kind of phenomenon in this country. Whenever there is some student unrest in this country, they want to suppress it without analysing the reasons behind it. They want to come with a big cudgel and say, 'Don't do this; it is because of personal motives' and so on and so forth.

A serious problem like this is being taken up at the fag-end of this Session. I do not know what amount of importance they are going to give to this motion because it has been moved by two Private Members. I wish Government had taken this up earlier in the Session.

We always say that the future is in the hands of the youth, in the hands of the students. We always address the students that they are going to be the builders of this country, they are going to mould the destiny of the country according to the aspirations of the people; whether it is the Rolling Plan or the Five-Year Plan, everything is meant for the next generation which is coming up. But it is a sad fact that the same promises were given when we were in colleges. Many of us belong to the lower side of forty. I do not blame the ruling party for these promises which were given. Dr. Chunder Saheb is not very old, he is younger than many Members here. As I was saying, when we were in colleges, great aspirations were aroused in us. We thought that, after 20 or 30 years, the country would flourish, at least 80 per cent of the population would get employment, we would be the creative builders of this country. But it is unfortunate that, even after 30 years, the same frustration is there. In fact, if you want me to put it plainly, with a doubled vigour this frustration has come into this country. I do not understand what it is that has prevented these people from solving the problem of students. That is precisely the main reason for the unrest. If it is a question of some personal gain, there may be some examination dispute, if it is a question of personal gain, there may be some dispute between professors and students or between Vice-Chancellors and students. But it is a common unrest. The reason for the general unrest in this country among the students is that they are not satisfied with the very system of education that we have....

MR. CHAIRMAN: Please try to conclude.

SHRI A. BALA PAJANOR: I will conclude, Sir. When we wrote our examinnation, they tested only our ignorance and not our intelligence. Even today in the IFS and IAS examination, they test the ignorance of the student population and not their intelligence. After writing too many examinations and taking Master's Degree, I feel that it is a great waste; unless we have erudition or make an analytical case study, it is a waste for us. They have not contemplated making a mass study about how to make one contribute his intelligence and creativeness. I must quote Burns to get the highest marks in English; I must quote Keynes to get the highest marks in Economics and I must quote Malthus to get the highest marks in population theory. They never ask Bala Pajanor what he thinks about these problems. That is the real malady. We have no understanding of the Indian student from the Indian perspective: we want to understand the Indian student or the southern student or the northern student from the perspective of Russia or the perspective of China or that of America or Europe because we have become a nation throughout, of borrowed intelligence.

You know that in those days the British people trained us to be good clerks in this country. Whenever British education is criticised it is said that because they wanted to govern us by means of brokers and clerks that kind of education was imparted to us. But, what are you trying to do? Because you have succeeded in the British system or the foreign pattern of administration you want to maintain the very system: you don't want any disturbance or hindrance to oppose you because you have tasted power so much that you want to keep to it in the same fashion as the British did. For this reason, here also, instead of clerks you are having B.D.Os and so on. But you do not want creative thinking. I know that there are some young Indian I.A.S. officers who have creative ideas which they want to contribute for the progress of this country. They must have nourished these aspirations from their school or college days, but when they want to express it in the administration, there will be some 'into' marks by the higher administrative authorities, saying 'this will not suit us' and they search for precedents.

[Shri A. Bala Pajanor]

So, would say, unless you allow the student population to have its say and express its creative thinking, and unless you allow them to come forward with solutions and take them up with all seriousness, forgetting your preaching mentality and your great sermonising mentality, this country will not come up. I am not pleading entirely for the student cause, but we always under-estimate the younger generation. This has been the case. I remember that at the age of eleven or so I used to feel that my parents or teachers are not able to understand what I think and what I want to present before them. The same is the case now. We have conservative ideas and a dominating element in us: always, the student is at fault: he must always listen to us, he must always take everything from us and we are not prepared to take anything from that side.

As far as unemployment is concerned, I remember that at many seminars many solutions were suggested but no action has been taken up those lines.

Now, student unrest is a *fait accompli*. We do admit it is a very big malady in this country. But, while solving it, it has to be solved by the students because we cannot only preach to the students: we must put the maximum confidence in their capacity to come out with good solutions. We must trust them and treat them as real citizens of this country because we say 'the future is in your hands'. I remember that Jawaharlal Nehru used to say that he was fond of the younger generation because they are going to rule us. But we are people who have come to Parliament. As far as my Party is concerned, I must say that I am proud of my leader-founder, the great Anna because he had a feeling for students. I will relate one solitary instance. This is not for Dr. Chunder alone but for all the Chief Ministers and Edueation Ministers and all the people in power.

In my college there was a student problem. There was a big agitation going on. When Anna went there to speak, he was booed but finally they started hearing him. Anna spoke for three hours. In those days he was suffering from the worst disease 'cancer.' He asked for water from the students but they refused to give him water. Anna retained his humility and love and affection for its students and said 'all right, you are refusing to give me water, but I will give my life for you so that I may be understand by you because I have a feeling that you are fighting for a cause according to your reasoning.' He spoke and, in the end, the very same students apologised and gave Anna water.

I have given this example because I am proud of my leader. And my present leader is following in the footsteps of Anna. Whoever goes beyond reality, if he practices what he preaches, it is O.K. for us.

As far as students are concerned, we are preaching the same things. If you are going to follow even 10 per cent of what you are preaching, I am sure the student unrest in this country will disappear.

With these words and with a great hope on our Education Minister, great Dr. Chunder Sahib, I conclude my speech. Once I happened to visit his House. I was very much moved by the art that he has created in his House. I saw a number of pictures there. I asked him when he bought those. He told me that it was all his creation. That day, I thought that he was a man of great creative spirit. I was moved and thrilled to see such a great artist being the Education Minister of our country. That day I thought that our education policy will get corrected under his leadership. I do not know what are the pinpricks that he has got in between. Let him bring his creative thinking in this field. Let him be bold and

accomplish all these things. I wish him all well.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for calling me to speak on this motion at this stage. As one who has been in the teaching and academic world for the last nearly three decades, I welcome this discussion. I hope, it proves useful and fruitful. I am only sorry that the discussion has come at the fag-end of the budget session. The motion talks about two things; it expresses concern at the growing student unrest in India and then it asks the Government—though I do not know why Government alone—to take appropriate steps to remove the causes of unrest. Now, Sir, Student unrest as such is not bad at all. Indeed, I am one of those who believe that some sort of student unrest is essential and it is to be welcomed because student unrest at root, at heart, is a spur to progress and development. If there is no unrest, we will all be dead: we want some kind of discontentment and restlessness, so that we can progress. So student unrest is not something which is to be taken a pessimistic view of, but if it takes a turn, which is violent, unproductive, purposeless, without any ideals, without any values, without any moral fervour, then, of course, there is something very "wrong in the State of Denmark", Sir, I was suggesting that student unrest to a certain extent indeed is a spur to progress and vitality. Moreover, let us not despair on another count, because student unrest is not something which is peculiar to our country. It has been a global phenomenon. I would only quote a few sentences of Renu Maheu, former Director General of UNESCO,—Dr. Chunder perhaps knows him—he said:

"This revolt of the young is sweeping across virtually every part of the world; it has taken on the form of an open dispute not only with universities but with society as a whole. With their need for absolutes, the young are less than ever able to tolerate the injustices and disorder of the world."

Sir, in a way, you might say that this is a global phenomenon, not a national problem.

Coming back to our national field, what does one see? One sees that the educational scene at home is far from satisfactory; indeed, it is very dismal. One finds that there are non-academic campuses everywhere. I must tell you, Dr. Chunder, most frankly that as a teacher, I do not feel very unhappy if universities are closed, because even if they are open, what do we do there? We do not teach, there is no experiment in education, there is all kinds of politicking, all kinds of disorder, all kinds of uneducational and unethical things happening there. If this is the order of the day, I sometimes feel, it is better, we do not have such educational institutions. But I am not arguing for a kind of anarchist attitude in education and saying that the institutions should be closed for ever. All I am saying is that the educational scene at home is not only giving non-academic campuses, but one finds, for example, one can say briefly —as I have no time at my disposal— there is no earnestness, there is no sincerity of purpose, no experimentation no exhileration, no sense of involvement or no sense of participation. It does not mean that there are no exceptions. There are good educational institutions, academic bodies, universities, teachers, students, professors, vice-chancellors, principals and management of course, but they are unfortunately only an exception. All this can go to prove that the rule unfortunately is that the academic campuses are becoming more or less, non-academic campuses.

What are the educational needs and requirements, nobody goes into it—neither the teachers, nor the Government nor the parents. As they do

[Prof P. G. Mavalankar]

not go into these things, one finds that the educational needs and requirements are not met. There is also indifference and lack of warmth and lack of understanding towards the younger people. Neither the teachers understand the students nor the parents understand the children and when there is no understanding and no warmth, how do you communicate? After all the entire experimentation in education is to experiment to communicate. If I cannot communicate with my children, if I cannot communicate with my students in my class and if I cannot communicate with my people in this country at all where is the education? Therefore, this lack of communication is also important. That is why there is student unrest. I would say briefly there are several causes and factors which are responsible for student unrest. One of them is inadequate funds. I am sure we will all be asking the Minister of Education to spend more. Then, of course, he will tell us—please vote for more as he will have to spend more. We will have to say that countries which spend proportionately much more on foreign policy matters, diplomacy on all kinds of things and on Defence and spend mighty little thing, precious little thing—on education such countries have no future, Mr. Chairman. So, I would say that inadequate funds, poor facilities, bad equipments of all sorts and inadequate and unsatisfactory teaching methods and wrong examination methods are giving no proper and good results.

Presently, more and more students say the right of copying is my birth right. I pity such students. But why does a student say so? Because he knows if he copies from somebody else, he passes. He does not have to use his intelligence. If he has to copy from somebody else, he passes. These are faulty examination methods. Therefore. U.G.C. and other bodies have to go into this problem. I know they are doing something like this. We must implement their good recommendations.

I would only say this that too much of politics and too little of education is the order of the day of our academic campuses, and that is why one finds student unrest. Moreover, uncertainty, insecurity and fear of unemployment these are haunting our young and blossoming generations of students—boys and girls.

We have to ask a question—who is responsible? We cannot merely say Government is responsible. Government is responsible but basically I have to say the responsibility has to be shared, not blame opportioned. I do not want to blame any one. But responsibility must be shared between teachers and managements—which include administration and vice chancellors and between parents, citizens, leaders and Governments. If you take all of them together and if you can assure the presence of good teachers, by and large. I tell you most of our problems of student unrest will go down. The malady is we do not have teachers of first choice. Teachers are teachers because they could not get jobs anywhere else. They have, therefore, become teachers. If there are teachers by first choice, by first love, then from them by first days of teaching, to the last days of teaching, teachers will deliver the goods because they love their subjects, they love their students and citizens. They love their profession, and thus because of challenging problems and because of such good atmosphere, the problem will be solved. Therefore, I would conclude by saying, if all goes right and proper, the deciding factor if at all one factor is there—important and responsible—I would say, it is the teacher. Then, what is the sum total of all this? In brief, I would say, the student unrest is something which we should not take a very despairing view. We should be vigilant, active, alert, and

we should do something quickly in concrete terms and not leave everything to the Government.

I do not agree with my friends Sarvashri Guptaji and Chandrappan. This mentality of finding fault with somebody else and not doing it ourselves is wrong and, therefore, I would tell the students and my young friends all over the country, that they, the students must rise in some kind of a refreshing revolt, a revolt against universities, against society, indeed against themselves. Unless they find something wrong in themselves and stand in revolt, I am sure it will not be possible to meet this challenge of student unrest. After all, we must understand that all this revolt is ultimately against a certain deteriorating quality of life that one sees in the world. It is not with the availability of comforts that the problem will be solved. If you have comfort in society, yet there is student unrest. Student unrest is now there because students have no fans, for example. If a good teacher teaches good students under a tree, I am sure there is no problem of fans and air conditioning. The question is, are there such good students? The question is, are there motivated students, and good teachers, earnest teachers? If you have these, I am sure, the problem of student unrest would be solved not from the point of eliminating student unrest but converting the bad unrest into a good, welcome, refreshing unrest.

श्री बृजभूषण तिवारी (खलीलाबाद) : अधिष्ठाता महोदय, यह प्रस्ताव जिसे आज माननीय कंवर लाल गुप्त जी ने सदन के सामने रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, क्योंकि एक तरफ तो यह संवेदनशील प्रश्न है और दूसरी तरफ यह चिंता का विषय है। हमारे कई मित्रों ने यहां पर जो विचार व्यक्त किये हैं या उन का जो दृष्टिकोण रहा है, उस के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा —यदि आप इस समस्या के नेगैटिव पक्ष को ही देखें या एकांगी दृष्टिकोण से इस को देखेंगे इस का निदान ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो इस समस्या का हल नहीं निकल पायेगा। यह सही है कि आज, यह समस्या केवल भारत की समस्या है या जब से जनता पार्टी की सरकार यहां आई है, तब से उठ खड़ी हुई है—ऐसा नहीं है, मैं इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता हूं।

जैसा कि हमारे मावलंकर जी ने कहा है, यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और यह युग की और उम्र की, दोनों की समस्या है। भारत के संदर्भ में मैं यह कहूंगा कि कांग्रेस के जमाने में जो शिक्षा नीति के बारे में उस का दृष्टिकोण रहा, वह हम को मालूम है। शिक्षा के बारे में जो पुरानी सरकार की दृष्टि थी, वह बिल्कुल ही अनएमेजीनेटिव थी, कोई कल्पना उस में नहीं थी और इसीलिए जो सुधार होने चाहिए थे शिक्षा नीति के ढांचें में, वे नहीं हुए। आमूलचूल परिवर्तन की बात बहुत कही गई थी परन्तु उस का कोई नतीजा नहीं निकला बावजूद इस के कि हम न तमाम कमेटियां, तमाम कमीशन बैठाए। तो एक तो पक्ष यह होगा कि जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार के आने में स्टूडेंट्स पावर का बहुत बड़ा योगदान है और इस नाते आज जो लोगों में असंतोष है और जो लोगों में नई आशाएं जगी हैं, उन को पूरा करने के लिए यह आवश्यक होगा कि जनता पार्टी की सरकार जो ठोस सुझाव दिये गये हैं, उन को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करे और उसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। इस के लिए आप को क्रान्तिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। तब कहीं जा कर इस समस्या का निदान हो सकेगा।

दूसरा पक्ष यह है कि आज जो हमारे कैम्पस हैं उनमें जो हालात हैं, उन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन हों और जो ठोस सुझाव हों, उन को क्रियान्वित किया जाए। मगर दूसरा जो पहलू है, उस के लिए मैं यह कहूंगा कि आज महाविद्यालयों के अन्दर, आज विश्वविद्यालयों के अन्दर जो वातावरण है, वह बहुत दूषित है और इस अस्वस्थ्य वातावरण में शिक्षा हो ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पर मैं उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों की बात आप को बताना चाहूंगा। पहले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेता हूं। वहां के उपकुलपति का जहां तक सवाल है, मुझे वहां के विद्यार्थियों ने बताया कि साल भर से विश्वविद्यालय के कुलपति विश्वविद्यालय में गये ही नहीं। दूसरा आप का बनारस का विश्वविद्यालय है। वहां पर उपकुलपति है ही नहीं। कई बार इस सदन में यह सवाल उठाया गया है और आज हमें यह मालूम हुआ है कि उस के लिए उपकुलपति मिल गये हैं और वे आज शायद वहां जाएंगे। और दो एक दिन में कार्यभार संभालेंगे। तो एक यह भी सवाल है कि उपकुलपति बहुत से तैयार होते ही नहीं, उपकुलपति मिलते नहीं और अगर मिलते हैं तो वे जाते नहीं हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि विद्यार्थियों की जो समस्या है, उस को ला एण्ड आर्डर का प्रश्न हम नहीं मान सकते परन्तु इस के साथ ही साथ मैं यह भी मानने को तैयार नहीं हूं कि जो लोग विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में रहें, वे इतने तुनक मिजाज टाइप के हों या इतने डरपोक हों कि वे वहां काम नहीं कर सके। उस विश्वविद्यालय का प्रशासन ऐसे लोगों के हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए। उन में नैतिक बल होना चाहिए, नैतिक साहस होना चाहिए। पहले भी विश्वविद्यालयों में उपकुलपति होते थे अगर वे अपने चरित्र से, अपने ज्ञान से, अपने आचरण से और अपने व्यक्तित्व से विद्यार्थियों को प्रभावित करते थे और विद्यार्थियों पर उन का असर पड़ता था। आज जो उपकुलपति चापलूसी से या तिकड़म से शासन करना

[श्री ब्रज भूषण तिवारी]

चाहते हैं उनमें नैतिक बल नहीं रहता है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों का उपकुलपति के स्थान के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ ही साथ सरकार का भी पक्ष आता है इस मामले में कि आज विश्वविद्यालयों का बन्द होना बिल्कुल आर्डर आफ दि डे हो गया है। पहले जब कभी विश्वविद्यालय बंद होता था तब ऐसा मालूम होता था कि मामला बड़ा गंभीर है। आज आये दिन विश्वविद्यालय बंद करदिये जाते हैं। बजाय इसके कि हम विद्यार्थियों की समस्या का कोई निदान ढूंढे, बजाय इस के कि हम उन से बातचीत करें, कोई रास्ता निकालें, इनको न कर के विश्वविद्यालय बंद कर दिये जाते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ठोस निर्णय लेना होगा। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय के उपकुलपति, वहां काम करने वाले, वहां के टीचर्स, वहां के विद्यार्थी समुदाय, सभी को इसके लिए जिम्मेदार मानना होगा।

मैं तो यह भी कहूंगा कि जिस समय विश्वविद्यालय बंद हो, उस अवधि का टीचर्स को वेतन भी नहीं देना चाहिए। उस अवधि में यह होता है कि सारा मामला एडमिनिस्ट्रेशन और विद्यार्थियों के बीच में हो जाता है, सरकार और विद्यार्थी मैदान में आ जाते हैं और अध्यापकों का जैसे कोई रोल ही नहीं रहता। इसलिए इस सम्बन्ध में भी हम कोई कारगर कदम उठाना पड़ेगा।

इसके साथ साथ, मान्यवर, कई वक्ताओं ने कहा कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मैं विद्यार्थियों में असंतोष का इसको कारण नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि आज विद्यार्थियों में कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है जिसके कारण ये सारी विकृतियां विद्यार्थियों में दृष्टिगोचर हो रही हैं। पिछली सरकार ने क्या किया? हमारे विद्यार्थियों के दिमाग को सिद्धान्तों का रेगिस्तान बना दिया। आज विद्यार्थियों के स्तर पर कोई बहस नहीं होती। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है कि आपसी विचार-विमर्श से ज्ञानवर्द्धन, वह वहां नहीं होता। वहां डिस्कशन नहीं होते, विचार विमर्श नहीं होते। अगर उनमें राजनीतिक चेतना हो, मार्क्सवाद, गांधीवाद और जो दुनिया के नये विचार हैं, उन पर वहां चिंतन हो तो उनके व्यक्तित्व में निखार आयेगा, उनके स्वभाव में परिवर्तन होगा और उनमें एक सेंस आफ रिस्पांसिब्लीटी आएगी। आज की शिक्षा तो केवल एक पासपोर्ट फार प्रिविलेज बन गयी है। उसके द्वारा सेंस आफ इन्वाल्मेंट नहीं आती। उसमें यह भावना नहीं आती कि उसे किस प्रकार का आगे जा कर आचरण करना होगा।

एक विद्वान श्री शुमाशर ने "स्माल इज ब्युटिफुल" में कहा था कि यह हिसाब लगाया गया है कि चीन में जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में एक साल शिक्षा पाता है उस पर तीन किसानों के साल भर का श्रम लगता है और अगर वही विद्यार्थी पांच साल यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करे तो उस पर 150 किसानों का साल भर का श्रम लग जायगा। अब विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय से निकलें, वह ऐसा बन कर निकले कि उसमें आत्म विश्वास न हो तो वह शिक्षा किस प्रकार की है। आज शिक्षा की ऐसी दुरवस्था है कि विद्यार्थी समुदाय किसी लायक नहीं रह जाता है। उसमें कांफिडेंस नहीं आता है। ऐसी शिक्षा को लागू करके जो कि उद्देश्यहीन हो, जिस शिक्षा का कोई उद्देश्य न हो, हम विद्यार्थी समाज को ज्यादा दिन तक शांत नहीं रख सकते। अगर इस समस्या का निदान ढूंढना है तो एक तरफ़ तो तात्कालिक काम करना है और दूसरी तरफ हमें दीर्घकालिक कदम उठाने होंगे। हम शिक्षा में आमूल परिवर्तन कर के ही, किसी ठोस रास्ते पर चला कर ही हम विद्यार्थियों की इस समस्या का निदान कर पायेंगे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, इस विषय में सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कहीं। मैं समझता हूं कि हमें यह देखना होगा कि यह बीमारी कहां है। बीमारी कहीं है और हम उसका निदान कहीं करें तो इससे बीमारी ठीक नहीं होगी, दब बेशक जाएगी। जिस प्रकार किसी को मलेरिया हो जाए, 104 डिग्री बुखार हो जाए तो उसे क्विनीन की गोलियां खिला दी जाती हैं। उससे मलेरिया दब जाता है लेकिन उससे मलेरिया के मच्छर नहीं मरते। इसी तरह से हम भी छात्र असंतोष का सही इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हम तो बस इतना देख पा रहे हैं कि आज छात्रों में कितना असंतोष है। जिस प्रकार एक थर्मामीटर यह बताता है कि कितना बुखार है, लेकिन बढ़ते हुए बुखार को वह नहीं रोक पाता, उसी तरह से हम यह देख रहे हैं कि छात्रों में कितना असंतोष है, उसके बढ़ने को नहीं देख रहे हैं। आप थर्मामीटर से यह तो पता लगा सकते हैं कि 1972 में छात्रों में कितना असंतोष था, 1976 में कितना था और अब 1978 में कितना है। यह असंतोष दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसमें वृद्धि होती जा रही है। जब तक आप इसका सही निदान नहीं कर पायेंगे, इसमें दिनों दिन वृद्धि होती जाएगी। और अपने देश का जो एक कंसट्रक्टिव तरीके से विकास कर सकते हैं वह डैस्ट्रक्टिव हो जाएगा। बचपन में हम पढ़ा करते थे कि एक लड़का है जो अपने सामने ईंटा ले कर खड़ा है। अब इस ईंटे से वह दो ही काम कर सकता है एक रचनात्मक कार्य और अगर उसको आप रचनात्मक कार्य नहीं बताते हैं तो वह किसी का शीशा तोड़ डालेगा इससे। आपकी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे। यदि ऐसा नहीं होता है तो लड़का विध्वंसक कार्य में लगेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता है।

छात्र असन्तोष का सब से पहला कारण यह है कि छात्रों के भविष्य की गारण्टी नहीं है। आज किसी भी छात्र के सामने उसके भविष्य की गारंटी नहीं है। इसके बारे

में मैंने बहुत पहले तीन सुझाव रखे थे। पहला यह था कि आप शिक्षा पद्धति को रोजगार उन्मुख बनाएं। राइट टू वर्क, काम पाने का अधिकार सब को होना चाहिए और इसको आप मूलभूत सिद्धान्तों में जोड़ें। संविधान में इस को आप स्थान दें। अगर रोजगार नहीं दे सकते हैं तो उसको आप बेरोजगारी का भत्ता देने की व्यवस्था करें। यदि यह भी नहीं कर सकते हैं तो इसी सदन में मैंने कहा था कि नौकरी पाने की जो आयु सीमा है, उसको आप खत्म कर दें। पच्चीस साल आयु सीमा आपने निर्धारित की हुई है। 24 साल आयु हो जाने के बाद वह दिन गिनना शुरू कर देता है, अब नौ महीने, अब आठ महीने, अब सात महीने बाकी रह गए हैं और वह पच्चीस साल का हो जाएगा और उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिल सकेगी। इस तरह से वह गिनता है जैसे उसको फांसी की सजा होने वाली हो। उसके लिए वह हर तरह के कर्म, कुकर्म करता है। सभी पालिटिशियंस के पास जाता है, घूस में रुपया देता है ताकि किसी तरह से उसको नौकरी मिल जाए। इस वास्ते मैं समझता हूं कि उसको आप रोजगार की गारण्टी दें और अगर आप उसको रोजगार नहीं देते हैं तो बेरोजगारी का भत्ता उसको आप दें। अगर भत्ता भी आप नहीं दे पाते हैं तो जो आयु सीमा आपने 25 साल तय कर रखी है उसको आप खत्म करें। 55 साल या 58 साल में आज सरकारी नौकर रिटायर होता है आखिरी एक दिन अगर बचता है तो भी उसको नौकरी पाने का अधिकार होना चाहिए। इससे उस में आशा बंधी रहेगी कि उसको नौकरी मिल सकती है और पच्चीस साल से ऊपर एक महीना या एक दिन अगर हो गया तो वह बूढ़ा नहीं समझ लिया जाएगा, नौकरी पाने के अयोग्य नहीं समझ लिया जाएगा।

दूसरी मूलभूत समस्या शिक्षा देने की है। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो, बामन का हो या हां भंगी का बेटा, सब को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। आज क्या होता है? टाटा, बिड़ला आदि के बच्चों के लिए अलग स्कूल हैं, बड़े बड़े अफसरों के बच्चों के लिए अलग स्कूल हैं और दूसरे लोगों को लिए अलग से जनरल स्कूल हैं। जो बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं वे कभी स्ट्राइक में भाग नहीं लेते हैं। एयर कंडिशंड स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के कभी तोड़-फोड़ नहीं करते हैं। यह इसलिए कि उनके पास भविष्य की गारन्टी है। केवल जनरल स्कूल और जनरल कालेजों में जो पढ़ते हैं वही तोड़ फोड़ करते हैं, वही स्ट्राइक करते हैं। वे जानते हैं कि नौकरी उनको नहीं मिलेगी तो वे पालिटिशियन बन जायेंगे, हीरोपन करेंगे। अब आप गांवों के स्कूलों की हालत को देखें। वहां चटाई तक नहीं होती है। बच्चों को घर से चटाई ले जा कर पढ़ना पड़ता है। जब वापिस घर जाते हैं तो उनको भूखों पेट रहना पड़ता है, मां बाप जाते ही कहते हैं कि बकरी चराने के लिए जाओ तब खाना मिलेगा। एक तरफ वे लड़के हैं जिन को भर पेट खाना नसीब नहीं होता है और दूसरी तरफ वे लड़के हैं जो एयरकंडिशंड कमरों में रहते हैं, एयर कंडिशंड स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन पर एक हजार रुपया महीना खर्च आता है। इस वास्ते जब तक समान और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी और शिक्षा पद्धति में बुनियादी परिवर्तन नहीं किया जाएगा छात्र असन्तोष बना रहेगा। थोड़े दिन के लिए इसको भले ही आप दबा दें लेकिन इसको जड़मूल से आप नष्ट नहीं कर सकेंगे। आप समिति बना देंगे, कैबिनेट कमेटी बना देंगे और कुछ देर के लिए आप इसको भले ही दबा दें लेकिन इसको आप जड़मूल से नष्ट नहीं कर सकेंगे।

मैं सहमत हूं कि शिक्षा को आप कनकरेंट लिस्ट में शामिल करें। इस में अभिभावकों का भी दोष है इसको मैं मानता हूं। मैं उदाहरण देता हूं। मैं पटना गया था। एक लड़का वहां परीक्षा दे रहा था। दूसरे दिन उसका गार्जियन उसको चिट पहुंचाने के लिए गया। चिट उस तक नहीं पहुंची तो लड़का अपने बाप को डांटने लगा और कहने लगा बापू आप रात भर क्या करते रहे? कहा तुम क्या करते थे? लड़के ने कहा हम तो सोये हुए थे। लड़के ने कहा कि आपको तो चिट तैयार कर लेनी चाहिए थी। तो आज जो मेरिटोरियस छात्र हैं वह भी पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं कि जब चुरा लिखा कर ही पढ़ना है और परीक्षा पास करनी है तो फिर मेहनत क्यों करें।

मूलभूत आधार है कि आप नौकरी की गारण्टी दीजिए, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, समान शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, और जैसा मैंने कहा इसके लिए आप एक किस्म के स्कूल कीजिये। बिहार में काफ़ी रोष है जब हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि पब्लिक स्कूल को खत्म नहीं करेंगे तो हमारे यहां बिहार में जो लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि पब्लिक स्कूल खत्म करो, एक तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू करो। लेकिन पता नहीं शिक्षा मंत्री महोदय ने क्यों कह दिया कि खत्म नहीं करेंगे। तो हम लोग जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री कह देते हैं कि एक तरह के स्कूल सब के लिए नहीं कर सकते हैं। इस बात को ले कर लोगों में काफ़ी असंतोष है और हम लोग उनके रोष को शांत नहीं कर पाते। आप कहिए अभी नहीं कर सकते हैं, दो, तीन साल बाद करेंगे। लेकिन आपको समान शिक्षा, एक किस्म के स्कूल, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और लड़कों के भविष्य की गारन्टी कीजिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

SHRI AMRIT NAHATA (Pali): Mr. Chairman, there is no quorum. (*Interruptions*) Let this debate continue,

SHRI KANWAR LAL GUPTA: The procedure is, it depends upon the Government whether the debate may be continued in the next session or not.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): We have no objection to this debate being continued in the next session for the number of hours that the Business Advisory Committee has set for it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: What is the Business Advisory Committee?

SHRI RAVINDRA VARMA: I am surprised the hon. Member is asking; "What is the Business Advisory Committee."

SHRI KANWAR LAL GUPTA: You say that the Government is ready to continue.

SHRI RAVINDRA VERMA: I do not want to be dictated. The Government has no objection to this debate being continued in the next session. But the question arises about the number of hours that has been set for it. The Business Advisory Committee has set four hours for this debate and it has not been exhausted. Therefore, I say that the remaining time can be devoted in the next session.

MR. CHAIRMAN: Let the debate continue for sometime now. Mr. Mukunda Mandal.

SHRI AMRIT NAHATA: After that, I should raise the quorum question. Is it?

SHRI KANWAR LAL GUPTA: You please say: " Let the debate continue in the next session." You say so.

MR. CHAIRMAN: We are considering it. Let the Speaker come. Mr. Mukunda Mandal.

*SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): Mr. Chairman, I will speak in Bengali, Mr. Chairman, Sir, at the very outset I thank Shri Kanwarlal Gupta and Shri C. K. Chandrappan for bringing forward this motion on student unrest in the country. This is a very important and serious subject facing the country and it has almost assumed the form of a national problem. Student unrest has manifested itself in the Universities and places of higher education in a very prominent manner today and it has set the entire community of educationists thinking very seriously as how to combat and face this challenge.

Sir, I feel that this student unrest has got two aspects. The first is that the students have got some genuine grievances and demands. Those demands are not being met. The Government and the educational institutions are not handing out the proper treatment to them. For example, the Vice-Chancellor of the Jawaharlal Nehru University had committed all possible atrocities on the students during emergency. The students had appealed to all quarters for removing him and when that did not meet with any success, then they entered upon agitations etc. This was a justified demand of the students and the Government should have considered that sympathetically and in the right spirits.

Then again, in the Plant Nagar University where students come to study not only from all corners of this country but even from foreign countries, the students do not have any democratic rights for forming a students union. It has also been seen that a particular class of pupils there

*The original speech was delivered in Bengali.

have conspired with the Vice Chancellor of that University to see that no students union is formed. I am not going into the details but I only want to say that because some such justified and valid demands of the students are ignored at many places, it gives rise to students unrest and agitations.

The second aspect of this problem is that the dissipated energy of certain class of rich and affluent students, the class which directs our society, also found expression in creating disturbances and unrest in the educational institutions. This expression of dissipated energy has found its way in our country from America and other Western countries.

Students agitations and students unrest is not something new to our country. Students unrest found expression even before independence. The student community had fought for the freedom of our country. That was confined to a particular objective. They had fought for the freedom of the country. But today we find that the students are showing unrest on certain minor grounds. Certain political parties are also inciting them for their own political gains. I do not say that this is the main cause of students unrest.

The main cause of students unrest is that as yet we do not have a proper and healthy system of education in this country. There must be a proper educational policy.

Then there is no definite curricula of education. These are constantly being changed, as a result of which the students find it very difficult to adjust themselves to these ever changing curriculum.

Another major flaw in our education system is that it is not job oriented. After completing their education the students are at a loss as what to do to earn a livelihood. The serious unemployment situation stare them in the face. If the education job oriented then the students could readily find some work after completing their education. The present system of education does not provide that.

Then, Sir, proper stress is not given on extra curricula activities in the educational institutions. Want of this facility also sows seeds of discontent and unrest in the students. I also feel that the blue films and the sexy and vulgar Hindi films are also making the students community adverse to education and encouraging them to lawlessness at later stages.

We have also seen that at Deoria in Uttar Pradesh, the students belonging to upper castes dragged out the belongings of Harijan students and set them on fire due to some flimsy communal bogey. How does this sort of mentality and sentiment develop among the students? There is politics involved in such incidents. A particular political party have their hands behind these incidents. They incite the students to violence for their petty political objectives—and to humiliate the Government of the day. This is deplorable and should be checked.

Shri Chandrappan said that this is a social problem. But I will say that this is not only a social problem but an economic problem also. It is rather a socio-economic problem. We cannot provide food to the students. In the Universities and places of higher education only students from upper middle classes and upper classes can mostly go. Students belonging to the lower strata of our society find it very difficult to go to institutions of higher education. This economic crisis results in frustration which is reflected in students unrest. Therefore so long as we do not treat this problem as a socio-economic problem and we cannot bring about a total transformation of society this problem will not be fully solved. Whatever steps are taken will at best be temporary measures.

[Shri Mukunda Mandal]

Another thing to be noted is that even today we are maintaining the high-cost public school system in education where children of affluent classes can only get admission. They are prevented from mixing with students from ordinary families. This dual system of education is unfortunately still prevalent in our country. This discriminatory treatment also carries seeds of student unrest at various stages. Therefore I believe that the hon. Minister of Education shall formulate such a fresh policy of education which will generate a consciousness among all the students of belonging to one nation and of patriotism. One class of students will not feel themselves aloof or distinct from another class of students. The students must be enabled to develop a national outlook. They must not develop a sectarian or provincial outlook. A proper educational policy is very necessary for this.

I am also of the view that the Government should assume full responsibility for education. In my State, West Bengal, the Government has made education free upto class sixth. Next year they propose to make it free upto class eighth. In this way gradually education must be made free over the State. The Government must assume full financial responsibility for this objective.

Shri Kanwarlalji had suggested that the responsibility of education should be shared by the Centre as well as the States. It should be in the hands of both *i.e.*, in the concurrent list. I do not agree with that suggestion. I feel that education should be in the hands of the States alone. Everybody's business is nobody's business. The States are the best judge of what system should be adopted in a particular State for imparting proper education to its students community. Education must remain a State subject.

A change must however be affected in the present system of education and examinations. The students have no faith in the present system. A studious and intelligent student sometimes may fail in an examination because he cannot answer a few selected questions properly, although he has undertaken sufficient study of the subject. The present system of examinations and evaluation is defective and it needs total overhaul. Renowned and experienced educationists should be consulted and asked to evolve a proper system of examination. On the one hand we should have job-oriented system of education and on the other hand, in the field of higher education we should have research-oriented system. I hope that the hon. Education Minister will consider all these aspects and suggestions and keep them in view when he will announce the future national education policy of the Government.

MR. SPEAKER: Now, Mr. Hukamdeo Narain Yadav.

SHRI RAVINDRA VARMA: He will continue in the next session. That was the last speaker.

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. . . .

MR. SPEAKER: I am told that there was an agreement that it will be continued in the next session.

श्री युवराज : स्पीकर महोदय, पिछले सेशन में रेलवे डिमांड्स पर आपने बहस करवाई थी, जो कि इस सेशन में कन्टिन्यू करनी थी, लेकिन आप ने वह बहस नहीं करवाई ।

MR. SPEAKER: That is not the matter now. Mr. Yadav.

श्री हुक्म देव नारायण यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, ...

MR. SPEAKER: Not to-day, but in the next session.

SHRI AMRIT NAHATA: Is it your ruling that the debate will continue during the next session?

MR. SPEAKER: Yes.

SHRI AMRIT NAHATA: Then I raise a question of quorum.

MR. SPEAKER: There is no necessity for quorum when we are adjourning.

CONTEMPT OF THE HOUSE

MR. SPEAKER: There was some disturbance caused by somebody*, on some local grievance, I am told. We have let him off with some warning.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. SPEAKER: The House stands adjourned till 11 hours tomorrow when it is to meet in a Joint sitting with the Rajya Sabha.

The House shall stand adjourned *sine die* upon the completion of the business to be considered at the Joint sitting.

19.07 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned **till Eleven of the Clock on Tuesday, May,* 16, 1978/*Vaisakha* 26, 1900 (*Saka*), *to meet in a Joint sitting with the Rajya Sabha.*

---

*Shri Sailander Kumar Mishra *alias* Suresh Kumar.

**Lok Sabha adjourned *sine die* after the conclusion of the Joint Sitting of the Houses of Parliament on May 16, 1978/Vaisakha 26, 1900 (Saka).

GMGIPND—Job I—1156 LS—JC 1630—31-7-78—880